



केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 63% किया

48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा, सरकार 10 हजार करोड़ खर्च करेगी

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर 2026। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। इससे लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नई दरें 1 जुलाई से लागू मानी जाएंगी। सरकार इसपर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

अप्रैल में 2% बढ़ा था डीए

इससे पहले सरकार ने अप्रैल में कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर में 2 फीसदी का इजाफा किया था। उस बढ़ोतरी के साथ डीए की दर 60% पर पहुंच गई थी। अब 3 फीसदी की ताजा बढ़ोतरी के बाद यह आंकड़ा 63 फीसदी हो गया है। सरकार के इस फैसले से त्योहारों के सीजन में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा और पिछले महीनों का एरिअर भी खाते में आएगा।



डीए बढ़ने से सैलरी में बढ़ोतरी बेसिक पे के आधार पर तय होती है...

- **मिनिमम बेसिक सैलरी वालों के लिए :** अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 है, तो 3% की बढ़ोतरी के हिसाब से हर महीने 540 का इजाफा होगा।
- **हायर पे-स्कैल वालों के लिए :** अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी की बेसिक सैलरी 56,100 है, तो उनकी मासिक सैलरी में लगभग 1,683 की सीधी बढ़ोतरी होगी।
- **एरियर का भुगतान :** चूंकि यह फैसला जुलाई से प्रभावी है, इसलिए कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का बकाया भी आगामी सैलरी के साथ दिया जाएगा।

साल में दो बार रिवाइज होता है भत्ता

केंद्र सरकार हर साल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में दो बार संशोधन करती है। पहला संशोधन आमतौर पर जनवरी से और दूसरा जुलाई से प्रभावी होता है। सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर महंगाई का आकलन करती है और उसी अनुपात में भत्ते बढ़ाने का निर्णय लेती है।

बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए मिलता है अलाउंस

डीए सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन के खर्च को संतुलित करने के लिए दिया जाने वाला अलाउंस है। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में तय होता है। वहीं, डीआर रिटायर्ड कर्मचारियों यानी पेंशनर्स को उनकी बेसिक पेंशन पर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों के असर को कम करना है।

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के लिए 7395 करोड़ की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने और गांवों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 7,395.55 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' (पीएम वीजीएसवाई) को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस परियोजना को मंजूरी दी है। वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,395.55 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2026-27 से 2030-31 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' (पीएम वीजीएसवाई) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को मंजूरी दी है। यह 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप, शासन व्यवस्था में बदलाव लाने वाली आधुनिक पहल है। इस योजना को 2026-27 से 2030-31 तक (यानी 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान) लागू करने की मंजूरी दी गई है। 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। जागरूकता बढ़ाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम से कम से कम 1 करोड़ नागरिक जुड़ेंगे।



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का कुल बजट 7,395.55 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये है। 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। जागरूकता बढ़ाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम से कम से कम 1 करोड़ नागरिक जुड़ेंगे।

खेल सामग्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लाई योजना, 18 सौ करोड़ मंजूर

केन्द्र सरकार 'खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुइड मैनुफैक्चरिंग' योजना लेकर आई है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को परियोजना के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये की मंजूरी किए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि यह योजना 2026 से 2033-34 की अवधि में लागू की जाएगी। योजना के कुछ प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे। योजना से घरेलू खेल सामग्री विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। निवेश, नवाचार और निर्यात को प्रोत्साहित मिलेगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती मिलेगी। योजना के तहत निवेश समर्थन और उत्पादन वृद्धि के लिए 1,130 करोड़ रुपये, अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों के प्रमाणन के लिए 105



करोड़ रुपये तय किए गए हैं। योजना के माध्यम से खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। लघु एवं मध्यम उद्यमों और मौजूदा विनिर्माण समूहों को मजबूत किया जाएगा। अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और कौशल विकास को समर्थन दिया जाएगा। वैश्विक बाजारों में भारतीय खेल सामग्री का प्रचार किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में कंटेनर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2039-40 तक लागू रहने वाली इस योजना का उद्देश्य भारत में विश्वस्तरीय कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना है। सरकार का अनुमान है कि इससे घरेलू कंटेनर उत्पादन क्षमता



लगभग दस गुना बढ़कर सालाना 7.5 लाख टीईयू हो जाएगी और 53,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं

अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के

फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कंटेनर भारत और दुनिया के व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। थोक वस्तुओं को छोड़कर निर्यात और आयात के लिए परिवहन किए जाने वाले लगभग सभी सामान कंटेनरों में ले जाए जाते हैं। उन्हीने कहा कि वैश्विक स्तर पर कंटेनर विनिर्माण कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित है और करीब 95 प्रतिशत उत्पादन एक ही देश में होता है। वैष्णव ने कहा, 'कंटेनर भारत और पूरी दुनिया में व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। थोक वस्तुओं को

छोड़कर निर्यात या आयात के लिए परिवहन किए जाने वाले लगभग सभी सामान कंटेनरों में ले जाए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर कंटेनर विनिर्माण अत्यधिक केंद्रित है और 95 प्रतिशत उत्पादन एक ही देश में होता है। इस भारी निर्भरता को देखते हुए शिपिंग लाइनें और शिपिंग कंपनियां लंबे समय से आग्रह कर रही हैं कि कोई दूसरा देश भी उभरे और कंटेनर विनिर्माण में मजबूत स्थिति स्थापित करे। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी की गई।

मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी

भोपाल, 28 अक्टूबर 2026। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 28 अक्टूबर को उनके नाम की घोषणा की। पुरी केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हैं। यह सीट केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उन्होंने 14 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर 12 नवंबर को मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए सामान्य स्थिति में 116 मतों का कोटा है। हालांकि, कांग्रेस विधायक मुकेश मल्लोत्र मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेगे। ऐसे में 229 विधायकों के आधार पर चुनावी गणित तय होगा और जीत का कोटा निर्धारित नियमों के अनुसार तय किया जाएगा। बीना विधायक निर्मला सप्रे की स्थिति भी अहम है। वे खुद को कांग्रेस में बताती हैं, लेकिन भाजपा के कार्यक्रमों में भी नजर आती रही हैं। दलबदल से जुड़े मामले के कारण उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनके वोट को लेकर तस्वीर साफ होने के बाद ही दोनों दलों की प्रभावी संख्या का सटीक आकलन हो सकेगा।



मतपत्र से हुए एमएलसी चुनावों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, मोदी ने कसा तंज

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों के चुनाव में कांग्रेस के एक भी सीट नहीं जीतने को लेकर बुधवार को पार्टी पर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, 'चार बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों पर चुनाव हुए। चुनाव मतपत्रों के जरिए कराए गए। अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं? 'प्रधानमंत्री को यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब विपक्षी दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। मतपत्रों से हुए चुनाव का उल्लेख करते हुए मोदी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाया।



राहुल गांधी पर सुधांशु त्रिवेदी का निशाना, बोले-जनता का समर्थन मेहनत से मिलता है, धूमने-फिटने से नहीं

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर 2026। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला आंदोलन चलाने की बात कहे जाने पर गहरा अफसोस जताते हुए आज कहा कि जब जनता एवं विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं और उनकी राजनीति को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि वह पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता एवं सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले आंदोलन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि जनता और विधायक उनके साथ नहीं हैं। त्रिवेदी ने दावा किया कि राहुल गांधी की राजनीतिक गतिविधियों को जनसमर्थन नहीं मिल रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी करीब दो हफ्ते सैर-सपाटा और तफरीह करने के बाद अब भारत की अर्थव्यवस्था में समस्याएं पैदा करने के लिए आंदोलन की बात कर रहे हैं। लेकिन न जनता उनके साथ है, न विधायक। उन्हें समझना चाहिए कि वह पूरी तरह नाकाम साबित हो चुके हैं। जनसमर्थन मेहनत से मिलता है, सैर-सपाटा करने से नहीं। भाजपा सांसद ने राहुल गांधी की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की जरूरत है।



स्पेन में हाई स्पीड ट्रेनें टकराईं, 64 की मौत कई डिब्बे मलबे में बदले, इन ट्रेनों की एवरेज स्पीड 200किमी/घंटे से ज्यादा

मैड्रिड, 28 अक्टूबर 2026। स्पेन के टोलेडो प्रांत में बुधवार को दो हाई स्पीड ट्रेनें टकराईं। झोड़ी न्यूज के मुताबिक, हादसे में 64 लोगों की मौत हो गई, जबकि 179 लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव के लिए इमरजेंसी और मेडिकल टीमों मौके पर पहुंचीं।

स्पेनिश मीडिया के मुताबिक, हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे मोरा और ओरगाज कस्बों के बीच हुआ। एक ट्रेन ने दूसरी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कई डिब्बे चुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद राजधानी मैड्रिड को दक्षिणी अंदालुसिया क्षेत्र से जोड़ने वाली रेल लाइन बंद कर दी गई। दोनों ट्रेनें सरकारी कंपनी रेनफे और निजी कंपनी इर्यो की थीं। इन ट्रेनों की



रफ्तार आमतौर पर 200 किमी/घंटे से ज्यादा होती है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने कहा कि इस हादसे की खबर

सुनकर वे सदमे में हैं। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और हादसे में प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। टोलेडो

मैड्रिड में ट्रेन यात्रियों का इंतजार बढ़ा

यह साफ नहीं है कि हादसा किस वजह से हुआ। जांच की जाएगी कि ट्रेन समय पर क्यों नहीं रुकी। क्या सिमल सिस्टम में खराबी थी या ड्राइवर ब्रेक लगाने में चूक गया, इसकी भी जांच होगी। जांच में यह भी देखा जाएगा कि टक्कर से पहले ये सिस्टम काम कर रहे थे या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, रेनफे ट्रेन का ड्राइवर अभी लापता है। ट्रेन ड्राइवरों के संगठनों ने हादसे को असामान्य बताया है। राजधानी मैड्रिड को जोड़ने वाली ट्रेन सर्विस बंद होने की वजह से यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मैड्रिड के स्टेशनों पर यात्री ट्रेनों के इंतजार में खड़े हैं। स्पेन में इसी साल जनवरी में भी इन्हीं दोनों कंपनियों की ट्रेनें टकराई थीं। हादसा अंदालुसिया के अदामुज के पास हुआ था। इसमें 46 लोगों की मौत हुई थी। Iryo कंपनी की हाई-स्पीड ट्रेन मालगासा से मैड्रिड जा रही थी। ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरी पटरी पर चले गए थे और सामने से आ रही Renfe की ट्रेन से टकरा गए थे। लोगों ने बताया था कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्हें भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ था।

के पास उर्दा शहर के मेयर मैनुअल गलान के इलाज और देखभाल के लिए एक स्पोर्ट्स हॉल तैयार रखने को कहा है।

चक्रवाती तूफान अर्नब से आंध्रप्रदेश में तबाही, 3 की मौत

57 हजार लोग शिपट, 50 ट्रेनें-21 प्लाइट रद्द, एमपी-यूपी में भी बारिश का अलर्ट...

विशाखापट्टनम, 28 अक्टूबर 2026। बंगाल की खाड़ी से उठ चक्रवाती तूफान 'अर्नब' आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। यहां 125 से 135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में 3 मौतें हुई हैं। राज्य के 31 घरों को नुकसान पहुंचा। 57 हजार लोगों को शिपट किया गया है। तूफान के कारण 50 ट्रेनें और विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर 21 प्लाइट्स रद्द की गईं। ओडिशा में भारी बारिश के चलते 16 जिलों में स्कूल बंद हैं। यहां 30 हजार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 4,000 साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं। विशाखापट्टनम में रात 27



अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे से 28 अक्टूबर की सुबह 3 बजे तक, यानी करीब 18 घंटे में 200mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। यह जुलाई में होने वाली औसत बारिश के डेढ़ गुना से ज्यादा है। यहां जुलाई में औसतन 133mm बारिश होती है।

आंध्र प्रदेश और ओडिशा : भारी से बेहद भारी बारिश, तेज हवाएं और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र : पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में बारिश का अनुमान। कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।

फिलीपींस दौरे पर राजनाथ ने अमेरिकी युद्ध सचिव हेगसेथ से रक्षा संबंधों पर वार्ता की

दोनों नेताओं ने 10 साल के भारत-अमेरिका डिफेंस फ्रेमवर्क की प्रगति पर फोकस किया

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिलीपींस में 13वें एडीएमएम-प्लस के मौके पर अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के साथ बातचीत की, जिसमें भारत-अमेरिकी रक्षा संबंधों की समीक्षा करके उन्हें और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। फिलीपींस के सेबू में कॉन्क्लेव के दौरान हुई बैठक में दोनों नेताओं ने 10 साल के रक्षा संबंधों के प्रेमवर्क में सैन्य प्रौद्योगिकी, सूचना साझाकरण और सह-निर्माण पर फोकस किया। बातचीत का मुख्य फोकस आपसी रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर था। रक्षा



मंत्री सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में हेगसेथ के साथ अपनी बातचीत को 'बहुत बढ़िया' बताया। उन्होंने कहा कि एडीएमएम-प्लस मीटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया के डेविड पीएम और डिफेंस

मिनिस्टर रिचर्ड मॉलेस से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा करने, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को सुलझाने करने पर अच्छी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने अपने 10 साल के इंडिया-अमेरिका डिफेंस फ्रेमवर्क की प्रगति पर चर्चा किया, जिससे मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंफार्मेशन शेयरिंग और को-प्रोडक्शन में स्ट्रेटजिक कवरेज को बढ़ावा मिला। हमारी मजबूत पार्टनरशिप एक फ्री, ओपन और सिम्बोरि इंडो-पैसिफिक के लिए एक नींव का पत्थर बनी हुई है।

बिहार विधान परिषद चुनाव में भाजपा को तीन सीटें, आठ में से पांच पर भूमिहार उम्मीदवारों की जीत या बढ़त



पटना, 28 अक्टूबर 2026। बिहार विधान परिषद की चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन सीटों के चुनाव परिणाम की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। उपलब्ध नतीजों और रज्जानों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी को तीन, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज को एक-एक सीट पर सफलता मिली है। सारा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय राहुल राज ने जीत दर्ज की है, जबकि तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी बढ़त बनाए हुए हैं। इन चुनावों में जातीय समीकरण भी प्रमुखता से उभरे हैं। आठ सीटों में से पांच पर भूमिहार समाज के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है या बढ़त बनाई है। चुनाव परिणामों के अनुसार, सत्तारूढ़ भाजपा-जदयू गठबंधन के खाते में चार सीटें आई हैं। इनमें तीन भाजपा और एक जदयू को मिली है। वहीं, राजद और जन सुराज को एक-एक सीट पर सफलता मिली है। दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रमुख दलों को चुनौती दी है। जातीय आधार पर देखें तो आठ में से पांच सीटों पर भूमिहार समाज के उम्मीदवार विजयी हुए हैं या जीत की स्थिति में हैं। इनमें तिरहुत शिक्षक सीट से भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह, पटना शिक्षक सीट से राजद के डॉ. संजीव कुमार सिंह, पटना स्नातक सीट से जदयू के नीरज कुमार, दरभंगा शिक्षक सीट से जन सुराज के डॉ. सुरेश प्रसाद राय और दरभंगा स्नातक सीट से भाजपा के सर्वेश कुमार शामिल हैं। इसके अलावा कोसी स्नातक सीट से भाजपा के डॉ. एनके यादव ने जीत दर्ज की है, जो यादव समाज से आते हैं। सारा शिक्षक सीट से विजयी निर्दलीय राहुल राज राजपूत समाज से हैं, जबकि तिरहुत स्नातक सीट पर बढ़त बनाए हुए निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी मल्लाह (निषाद) समाज से आते हैं। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद के डॉ. संजीव कुमार सिंह ने भाजपा के नवल किशोर यादव को 1,057 मतों से हराया है।

संपादकीय

राष्ट्र निर्माण में नई पीढ़ी की भूमिका

जे न जी और जेन अल्फा की पीढ़ी को समझते समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, अपितु यह है कि वे सीख कहाँ से रहे हैं? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तक से नहीं सीखता। वह अपने आसपास के व्यवहार से भी सीखता है, परिवार से सीखता है, मित्रों से सीखता है, शिक्षक से सीखता है और आज पहले से कहीं अधिक डिजिटल दुनिया से सीखता है। वह जो देखता है, सुनता है और अनुभव करता है, धीरे-धीरे उसके विचार और व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में शिक्षा की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक गंभीर एवं बढ़ जाती है। गत दिनों में यह देखने में आया है कि आज की पीढ़ी अधिकारों की चर्चा बहुत करती है, अधिकारों के बारे में जागरूक करना आवश्यक भी है। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें शिक्षा का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है और समान अवसर पाने का अधिकार है। लेकिन क्या हम उन्हें उतनी ही गंभीरता से उनके कर्तव्यों के बारे में भी बता रहे हैं? या वर्तमान पीढ़ी को उनके कर्तव्यों का ज्ञान है? अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र केवल अधिकारों की व्यवस्था नहीं है। वह अधिकार और कर्तव्य के संतुलन पर चलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए आज की पीढ़ी को यह सिखाना आवश्यक है कि उसे क्या मिलना चाहिए, इसके साथ यह भी समझाना कि समाज और राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है। विद्यार्थियों को यदि केवल यह बताया जाए कि उनके अधिकार क्या हैं, लेकिन यह न बताया जाए कि दूसरों के भी अधिकार हैं और उन अधिकारों का सम्मान करना उनका कर्तव्य है, तो अधिकार की चेतना अधूरी रह जाएगी। अपने विचार रखने का अधिकार है तो दूसरों के विचार को सुनने का दायित्व भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उसके जिम्मेदार उपयोग का कर्तव्य भी है। इंटरनेट तक पहुंच है तो डिजिटल माध्यम का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी है। आज इंटरनेट मीडिया ने इस संतुलन को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। एक विलक में कोई सूचना हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। ऐसे में आज के विद्यार्थी को यह भी सिखाना होगा कि हर सूचना सत्य नहीं होती, हर वायरल सामग्री साझा करने योग्य नहीं होती और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती।

यही वह स्थान है जहां संस्कार और मूल्य शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनते हैं। संस्कार का अर्थ केवल परंपराओं का पालन करना नहीं है। संस्कार का अर्थ है-सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता, दूसरों के प्रति सम्मान, अनुशासन, संवेदनशीलता, सहानुभूति सत्य के प्रति आह्लाद और अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता। मूल्य व्यक्ति को यह तय करने में सहायता करते हैं कि किसी परिस्थिति में उसके लिए सही आचरण क्या होना चाहिए। जब अधिकारों के साथ संस्कार और कर्तव्य जुड़ते हैं तो अधिकार केवल व्यक्तिगत लाभ का माध्यम नहीं रहता, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण की शक्ति बन जाता है। किसी भी अधिकार की वास्तविक शक्ति इस बात में है कि उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। यदि अधिकार का उपयोग केवल अपने हित के लिए हो और उससे समाज के हित की उम्मेदा होने लगे तो वही अधिकार टकराव का कारण बन सकता है। लेकिन जब अधिकार के साथ कर्तव्य और संस्कार जुड़ते हैं तो वही अधिकार राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन जाता है। एक जागरूक युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा, लेकिन साथ ही सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा भी करेगा। वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान भी करेगा। वह प्रश्न पूछेगा, लेकिन तथ्यों को समझने का प्रयास भी करेगा। इसलिए बच्चों को अधिकारों की जानकारी देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उन्हें यह समझाना भी है कि अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। जेन जी और जेन अल्फा के सामने सबसे बड़ी चुनौती शायद सूचना की कमी नहीं, बल्कि सूचना की अधिकता है। पहले बच्चे के सीखने के प्रमुख केंद्र घर, विद्यालय और समाज थे। आज इन तीनों के साथ डिजिटल दुनिया भी एक शक्तिशाली शिक्षक बन चुकी है। यह डिजिटल शिक्षक हमेशा सही जानकारी देगा, यह जरूरी नहीं है। किसी वीडियो की लोकप्रियता उसकी सत्यता की गारंटी नहीं है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की बात अंतिम सत्य नहीं हो सकती। एआइ से प्राप्त उत्तर को भी विवेक की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। इसलिए आज की शिक्षा को केवल जानकारी देने वाली शिक्षा नहीं, बल्कि विवेक विकसित करने वाली शिक्षा बनना होगा। बच्चे को उत्तर बताने से अधिक महत्वपूर्ण है उसे सही प्रश्न पूछना सिखाना। उसे यह सिखाना आवश्यक है कि किसी सूचना पर विश्वास करने से पहले वह सोच देखे, तथ्य जांचे और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझे। यही आलोचनात्मक चिंतन आगे चलकर उसे कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। शिक्षा की असली परीक्षा तब होती है, जब जीवन हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति रखता है जिसका उत्तर किसी पुस्तक के अध्याय में सिधे नहीं मिलता। संकट के समय व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है। असफलता के समय स्वयं को संभालना पड़ता है। भ्रम की स्थिति में सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। दबाव में भी मूल्यों पर टिके रहना पड़ता है। ऐसे समय में केवल डिग्री काम नहीं आती। काम आता है वह विवेक, धैर्य, अनुशासन और समस्या समाधान की क्षमता, जो शिक्षा ने व्यक्ति के भीतर विकसित की है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता नहीं हो सकता। उसका उद्देश्य जीवन की परीक्षा के लिए भी तैयार करना है।



ललित गर्ग
 एडिटर, अम्बिकापुर

भारत की संस्कृति में माता-पिता को देवतुल्य माना गया है। यहीं कहा गया है- 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।' जिस देश में माता-पिता के चरणों में स्वर्ग देखने की परंपरा रही हो, उसी देश में यदि वृद्धावस्था में माता-पिता अपने ही घर में उमेशा, अपमान, अकेलेपन और असुरक्षा का दर्श झेलने को विवश हों, तो यह केवल पारिवारिक कथित नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना के सामने खड़ा एक गंभीर प्रश्न है। जिस बुजुर्ग ने अपनी संतान के भविष्य के लिए वर्तमान को खपा दिया, यदि उसी संतान के पास उसके बुढ़ापे के लिए समय, संवेदना और स्नेह न बचे, तो विकास की चमक के बीच मानवीय मूल्यों का अधेरा साफ दिखाई देता है। ऐसे समय में केरल विधानसभा द्वारा अक्टूबर 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण से संबंधित व्यापक विधेयक पारित किया जाना एक आशाजनक पहल है। यह कानून की किताब में जुड़ा एक नया अध्याय भर नहीं, बल्कि बुजुर्गों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और भरोसे का नया सूर्योदय बनने की क्षमता रखता है। भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों की संख्या लगभग 23 करोड़ और 2050 तक 34 करोड़ से अधिक हो सकती है। यह बदलती जनसांख्यिकी हमें चेतावनी भी देती है और अवसर भी। किफ़्त्या विज्ञान की प्रगति तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं ने मनुष्य की आयु बढ़ाई है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमने जीवन की बढ़ती अवधि को गरिमापूर्ण बनाने की तैयारी भी की है? सिर्फ लंबी उम्र उपलब्धि नहीं

है, उस उम्र में सम्मान, आत्मनिर्भरता और अपनापन बनाए रखना ही वास्तविक उपलब्धि है। केरल की इस पहल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यह बुजुर्गों की समस्याओं को केवल परिवार की निजी जिम्मेदारी मानकर छोड़ देने के बजाय सामाजिक और संस्थागत दायित्व के रूप में देखती है। विधेयक में वरिष्ठ नागरिकों के साथ शारीरिक एवं मानसिक दुर्व्यवहार, क्रूरता और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें बेसहारा छोड़ने जैसे कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ संरक्षण इकाइयों, देखभाल केंद्रों के नियमन, देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण और शिकायतों के निवारण जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है। साइबर धोखाधड़ी से बचाव तथा बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों के अधिकार जैसे विषयों को समाज देना भी बदलते समय की जरूरतों को समझने का संकेत है। इस पहल का मूल संदेश स्पष्ट है-बुजुर्गों की सेवा सद्भावना का विषय अवश्य है, लेकिन उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना सामाजिक व्यवस्था का अनिवार्य दायित्व है। इस विधेयक की सबसे संवेदनशील अवधारणा है- 'एजिंग इन प्लेस', अर्थात् बुजुर्गों को यथासंभव उनके अपने घर और परिचित परिवेश में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना। वृद्धाश्रमों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन माता-पिता के लिए घर का एक कमरा भी तब अधिक मूल्यवान होता है, जब उम्र में अपनत्व की गर्माहट हो। बुजुर्गों को केवल भोजन, दवा और बिस्तर नहीं चाहिए, उन्हें बातचीत करने वाला साथी, उनकी बात सुनने वाला कान, उनके अनुभवों को समझने वाला मन और उनके अस्तित्व को



स्वीकार करने वाला परिवार चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पर कई बार आर्थिक अभाव से अधिक भावनात्मक अभाव पीड़ा देता है। जिस घर में बुजुर्गों की आवाज अनसुनी हो जाती है, वहाँ दीवारें तो रहती हैं, लेकिन परिवार की आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। आज संयुक्त परिवारों का विघटन, महानगरों की भागदौड़, विदेशों की ओर पलायन और बढ़ती व्यक्तिवादी प्रवृत्ति ने बुजुर्गों के जीवन को कठिन बनाया है। कभी दादा-दादी और नाना-नानी परिवार की जीवंत पाठशाला होते थे, उनकी कहानियों में इतिहास, अनुभवों में विवेक और आशीर्वाद में जीवन की पूँजी मिलती थी। आज उसी अनुभव-संपदा को कई बार अनुपयोगी समझ लिया जाता है। संपत्ति के लिए माता-पिता पर दबाव डालना, उनकी जमा-पूँजी पर अनुचित अधिकार जमाना, बीमारी में उन्हें अकेला छोड़ देना अथवा उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। यह कैसी विडंबना है कि जिन हाथों ने बच्चों को चलना सिखाया, उन्हीं हाथों को बुढ़ापे में सहारे के लिए तरसना पड़े! केरल का विधेयक इस समस्या के समाधान की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें बेसहारा छोड़ने पर तीन वर्ष तक के कारावास तथा 50 हजार रुपये तक के

जुर्माने का प्रावधान है। देखभाल केंद्रों के पंजीकरण, देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण, शिकायतों के निवारण और साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएँ भी प्रस्तावित हैं। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सा संबंधी पूर्वनिर्धारित निर्णयों, कानूनी सहायता और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच को महत्व दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा ने यह विधेयक 26 अक्टूबर 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया है, इसे कानून के रूप में लागू होने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस पहल का एक दूरदर्शी पक्ष 'सिल्वर इकोनॉमी' की अवधारणा भी है। बुजुर्गों को केवल सहायता प्राप्त करने वाले नागरिकों के रूप में नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके अनुभव, ज्ञान, कौशल और जीवन-दृष्टि का उपयोग शिक्षा, परामर्श, सामाजिक सेवा, उद्यमिता और सामुदायिक विकास में किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति का अर्थ प्रतिभा की समाप्ति नहीं, बल्कि जीवन की दूसरी पारी का आरंभ भी हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज उन्हें बोझ नहीं, अपनी अमूल्य पूँजी माने। पेड़ जब पुराना होता है, तब भी उसकी छाया कम मूल्यवान नहीं हो जाती। इसी तरह अनुभव की परिपक्वता किसी भी राष्ट्र की विकास-यात्रा की दिशा दे सकती है। अब समय है कि केंद्र सरकार के साथ दूसरे राज्य भी केरल की इस पहल से प्रेरणा लें। केंद्र के माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा हो तथा आवश्यकतानुसार उसे और सशक्त बनाया जाए। राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों के

करवा चौथ के व्रत की सार्थकता



प्रोफेसर शामलाल
 कोशल रोहतक, हरियाणा

पौराणिक परंपराओं के मुताबिक हमारे देश में पत्नियों द्वारा पतियों के कल्याण एवं दीर्घायु के लिए कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत रखने का रिवाज है। इस दिन पत्नियां सात दिन खाना तो दूर की बात पानी की बूंद भी नहीं पीती। शाम को करवा चौथ की कथा सुनती है रात को चंद्रमा के निकलने पर उनका पति ही व्रत खोलने के लिए जल पिलाता है। कहा जाता है जब पुराने समय में पत्नियों और बच्चों की सुरक्षा का काम पतियों के जिम्मे होता था तब साल में एक विशेष दिन करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पतियों की दीर्घायु के लिए पत्नियां परमात्मा से प्रार्थना करती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है। कुछ लोगों का मानना है कि पत्नियों द्वारा पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत रखने तथा पानी तक भी न पीना पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को जलील करने का एक तरीका है। जब पति शराबी कबाबी हो, पत्नी के साथ मारपीट करता हो, आमदनी का एक बहुत बड़ा भाग शराब, वेश्यावृत्ति आदि में खर्च देता हो और घर का गुलाम करने में तत्कलीफ होती हो, कोई पत्नी ऐसे गैर जिम्मेदार पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर सारा दिन भूखी क्यों मरेगी? पूछा जा सकता है कि पुरुष के भले के लिए स्त्री ही कुछ न कुछ करती है, पुरुष स्त्री के लिए क्यों ना करें! आज जमाना बदल गया है। करवा चौथ का व्रत पहले की



तरह प्रासंगिक नहीं। वैसे तो कोई भी रखा गया व्रत स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति के लिए उपयोगी होता है। लेकिन इस व्रत को रखना पति पत्नियों के लिए आजकल संभव नहीं। आज के कामकाजी पति-पत्नी कई बार एक जगह काम नहीं करते जिस से पति लोग अपनी पत्नियों को व्रत नहीं खुलवा सकें। और अगर एक जगह पर भी तैनात हो तो दोनों के काम करने के समय अलग-अलग हो सकते हैं जिसकी वजह से करवा चौथ का व्रत रखना संभव नहीं। आजकल के पति-पत्नी आम तौर पर छोटी-मोटी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनमें आपसी ईर्ष्या, अविश्वास, अहंकार, तर्करा, टकराव, सहयोग तथा समर्पण भावना का अभाव होता है ऐसे में पत्नी अपने पति के हित के लिए व्रत रखने में असहज महसूस करती है। बेशक आजकल कुछ पति पत्नियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं लेकिन इसके बावजूद भी इस व्रत की महत्ता उतनी नहीं रह

जाती। इस के अलावा इस व्रत को रखना पत्नी के लिए इसलिए भी अनावश्यक हो जाता है क्योंकि वह आर्थिक तौर पर स्वावलंबी है और सुरक्षा हेतु पति पर निर्भर नहीं करती। बेशक हमारे देश में कुछ औरतें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, इस दिन वह खूब हर श्रृंगार करती हैं, पूजा पाठ करती हैं कांता पति, तथा ससुराल वाले उन्हें! इस दिन उपहार भी देते हैं परंतु क्योंकि पति-पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार, वफादार, समर्पित तथा सदनशील नहीं होते अतः इस व्रत का कोई फायदा नहीं। अगर कोई पत्नी किसी कारण से व्रत को ना रखना चाहे तो उसे मजबूर बिचकूल नहीं करना चाहिए। अगर पति-पत्नी का आपस में दिल में प्रेम, विश्वास, सम्मान, सहयोग, वफादारी ईमानदारी तथा समर्पण भावना हो तथा किसी तीसरे में दिलचस्पी न हो तो वे का व्रत रखे बिना भी एक दूसरे की दीर्घायु तथा कल्याण हेतु सहायक साबित हो सकते हैं।

पति-पत्नी के पवित्र रिश्तों का पर्व है करवा चौथ

भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहां साल के सभी दिनों का महत्व होता है तथा साल का हर दिन पवित्र माना जाता है। भारत में करवा चौथ हिन्दुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चन्द्रमा दर्शन के बाद सम्पूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलायें करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। यह व्रत लगातार 12 अथवा 16 वर्ष तक हर वर्ष किया जाता है। अवधि



पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्घाटन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवनभर इस व्रत को कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल महिलाओं द्वारा अपने पतियों के लिए किया जाता है और यह न केवल एक त्योहार है बल्कि यह पति-पत्नी के पवित्र रिश्तों का पर्व है। कहने को तो करवा चौथ का त्योहार एक व्रत है लेकिन यह नारी शक्ति और उसकी क्षमताओं का सवरंजित उद्घाटन है। क्योंकि नारी अपने दृढ़ संकल्प से यमराज से भी अपने पति के प्राण ले आती है तो फिर वह क्या नहीं कर सकती है। आज के नये

जमाने में भी हमारे देश में महिलायें हर वर्ष करवा चौथ का व्रत पछले की तरह पूरी निष्ठा व भावना से मनाती है। करवा चौथ सभी विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक पत्नियाँ अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना पानी पिए और कुछ भी खाए व्रत रखना आसान नहीं है, लेकिन सोही पत्नियाँ अपने पति के प्रति पूरे प्रेम और सम्मान के साथ ये सभी रस्में निभाती हैं। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचन्द्र गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है। करवा चौथ में दिन भर उत्थास रखकर रात में चन्द्रमा को अर्घ्य देने के उपरान्त ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथव्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही

मनाती है। लेकिन अधिकतर स्त्रियाँ निराहार रहकर चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। सार्यकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियों व पति के माता-पिता को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। अपनी सासूजी को वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद दें। यदि वे न हों तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करें। इसके पश्चात स्वयं व परिवार के अन्य सदस्य भोजन करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात् उस चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है। उस दिन प्रातः स्नान करके अपने पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिनभर निराहार रहें। उस दिन भगवान शिव-पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करें। शुद्ध घी में आटे को सेंककर उसमें शकर अथवा खांड मिलाकर नैवेद्य हेतु लड्डू बनाएं। काली मिट्टी में शकर की चासनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के अथवा तांबे के बने हुए अपनी सामर्थ्य अनुसार 10 अथवा 13 करवे रखें। करवा चौथ के बारे में व्रत करने वाली महिलाएं कछानी सुनती है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर

द्रोपदी बहुत परेशान थीं। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा बहन। इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकरजी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान-प्रदान किया जाता है। जो आपसी प्रेम-भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास-ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकरजी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बताया। आधुनिक होते समाज में भी महिलायें अपने पति की दीर्घायु को लेकर सचेत रहती हैं। इसीलिए ये पति की लम्बी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखना नहीं भूलती हैं। पत्नी का अपने पति से कितने भी मिले-जिस्के रहे हो मगर करवा चौथ आते-आते सब भूलकर वो एकाग्र चित्त से अपने सुहाग को लम्बी उम्र की कामना से तब जरूर करती है। करवा चौथ शब्द करवा अर्थात् मिट्टी का बर्तन और चौथ अर्थात् चतुर्थी से मिलकर बना है। इस पर्व पर मिट्टी के करवे का विशेष महत्व होता है। सभी विवाहित महिलाएं पूरे वर्ष इस त्योहार की प्रतीक्षा करती हैं और इसकी सभी रस्मों को श्रद्धा के साथ निभाती हैं।



लक्ष्मी नारायण लहरे
 सारंगढ़, छत्तीसगढ़

समाज आज भी आपके सरल, सशक्त नेतृत्व को भुलना नहीं याद करता है ...चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए... इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए... सरल व सशक्त व्यक्तित्व के धनी किसान पुत्र त्रिलोचन लहरे ...

जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब हम कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीखते हैं, तभी वह कंधा हमेशा के लिए छूट जाता है। बचपन में पिता के पास रोंकर अपनी बात मनवा लेना सहज होता है, पर जवानी में उसी पिता से दिल की बात कह पाना सबसे कठिन हो जाता है। पिता बिना कहें ही सब समझ जाता है। वह पुत्र की हर अनकही इच्छा को पूरा करने का अंतिम प्रयास तक करता है। यही तो पिता का सच्चा फर्ज है, यही भारतीय किसान परिवार की परम्परा है। बाबूजी त्रिलोचन लहरे इसी परम्परा के सच्चे वाहक थे। अभी तो मैंने अपनी जवानी ही संभाली थी, बचपन की गलियों से निकलकर दुनिया को समझने की कोशिश ही कर रहा था। आपके जीवन के कुछ अनागढ़ लम्हे, आपकी कुछ बातें, आपकी कुछ सीखें आज भी हृदय में अंगूठे बनकर ठहरी हैं, जो कभी सुखती नहीं। जब से मैंने होश संभाला, आपको खेत-खलिहान, घर-द्वार और सामाजिक सरोकारों में निरंतर संघर्ष करते हुए ही पाया। आपको कभी थकते हुए नहीं देखा। सुख हो या दुःख, आप कभी पीछे नहीं हटे। बस मुस्कुराकर अपनी मजिल की ओर चलते रहे। जब से आपने होश संभाला, घर की, परिवार की और समाज की पूरी जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई। और जब समय आया कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँ, आप ऐसे रूठ गए कि फिर लौटकर नहीं आए। आपने कुछ नहीं कहा, और मैं आपसे अंतिम बार बात भी नहीं कर पाया। एक पुत्र और पिता के बीच अंतिम संवाद भी नहीं हो पाया, इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है? बाबूजी, अभी मैं इतना सशक्त नहीं हो सका था। आपका जाना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए अपरुणीय क्षति है।

जीवन परिचय-
एक संघर्ष की गाथा
 आपका जन्म सारंगढ़ जिला मुख्यालय के।कोसीर नगर के सशक्त किसान परिवार में 01 जुलाई 1963 को हुआ था। आपके पिताजी स्व. मुन्ना दास लहरे कोसीर अंचल के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत थे। आपकी माता श्रीमती रामबाई एक सरल जिम्मेगी थीं। परिवार में आप अंश्ले थे, पर गुणोपगुण क्षति है।

लिए समर्पित संरक्षण इकाईयें, सुलभ शिकायत व्यवस्था, निःशुल्क कानूनी सहायता, घर पर स्वास्थ्य सेवाएँ और सुरक्षित सामुदायिक केंद्र विकसित किए जाएँ। पुलिस, अस्पतालों, बैंकों और स्थानीय निकायों में बुजुर्गों की समस्याओं के त्वरित समाधान की व्यवस्था हो। साथ ही, विद्यालयों और महाविद्यालयों में पीढ़ियों के बीच संवाद तथा परिवारों में संवेदनशीलता विकसित करने के अभियान चलाए जाएँ। कानून अपराध होने के बाद दंड दे सकता है, लेकिन संस्कार अपराध की नौबत आने से पहले ही रोक सकते हैं।

अंततः बुजुर्गों की सुरक्षा का प्रश्न केवल एक आयु-वर्ग के कल्याण का विषय नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा का निर्धारक है। आज जो युवा हैं, वे कल वरिष्ठ नागरिक होंगे। इसलिए बुजुर्गों के लिए बनाई गई संवेदनशील व्यवस्था वास्तव में हमारे अपने भविष्य की सुरक्षा है। विकसित भारत और विश्वगुरु भारत का स्वप्न तभी सार्थक होगा, जब आर्थिक समृद्धि के साथ मानवीय संवेदना, तकनीकी प्रगति के साथ नैतिक चेतना और आधुनिक जीवन के साथ पारिवारिक आत्मीयता भी विकसित होगी। केरल की पहल एक नई रोशनी का संकेत है, लेकिन इस रोशनी को देश के प्रत्येक घर तक पहुँचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें ऐसा भारत बनाना है, जहाँ वृद्धावस्था विवशता नहीं, सम्मान का काल हो। यहाँ बुजुर्गों को अपने ही घर में पराया न होना पड़े। और जहाँ उनकी आँखें संतान की प्रतीक्षा में नहीं, उसके प्रेम और उपस्थिति में चमकें। आखिर जिस समाज की जड़ें अपने बुजुर्गों के अनुभवों से जुड़ी रहती हैं, उसकी विकास-यात्रा के तूफानों में भी स्थिर रहने की संभावना अधिक होती है। यही सच्चे अर्थों में संस्कारित, समृद्ध और विकसित भारत की पहचान होगी।

संस्मरण

गए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही प्राथमिक बालक-कन्या शाला में हुई। आप केवल 6वीं कक्षा तक ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर पाए, क्योंकि घर में बड़े होने के कारण मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। आपका विवाह जाँगीर-चाँपा जिले के वर्तमान सही जिले के ग्राम बचौद के कृषक परिवार, पीकुराम बंचोरे की मंझली पुत्री नीरा बाई से हुआ। विवाह के बाद तो पूरा परिवार का भार आप पर ही टिक गया। तब से लेकर अंतिम सांस तक आपने घर, परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया।

सामाजिक व्यक्तित्व-कोसीर की माटी का सच्चा सपूत...
 सामाजिक दृष्टि से यदि त्रिलोचन लहरे जी के व्यक्तित्व को देखें तो वे केवल एक किसान नहीं, एक संस्था थे। आप सरल, सहज और मिलनसार स्वभाव का भार आप पर ही टिक गया। किसी के सुख-दुःख में सबसे पहले पहुँचने वाले आप ही होते थे। खेत में हल चलाना, फसल बोना, फिर उसी फसल को लेकर दुनिया को समझने की कोशिश ही कर रहा था। आपके जीवन के कुछ अनागढ़ लम्हे, आपकी कुछ बातें, आपकी कुछ सीखें आज भी हृदय में अंगूठे बनकर ठहरी हैं, जो कभी सुखती नहीं। जब से मैंने होश संभाला, आपको खेत-खलिहान, घर-द्वार और सामाजिक सरोकारों में निरंतर संघर्ष करते हुए ही पाया। आपको कभी थकते हुए नहीं देखा। सुख हो या दुःख, आप कभी पीछे नहीं हटे। बस मुस्कुराकर अपनी मजिल की ओर चलते रहे। जब से आपने होश संभाला, घर की, परिवार की और समाज की पूरी जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई। और जब समय आया कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँ, आप ऐसे रूठ गए कि फिर लौटकर नहीं आए। आपने कुछ नहीं कहा, और मैं आपसे अंतिम बार बात भी नहीं कर पाया। एक पुत्र और पिता के बीच अंतिम संवाद भी नहीं हो पाया, इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है? बाबूजी, अभी मैं इतना सशक्त नहीं हो सका था। आपका जाना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए अपरुणीय क्षति है।

वह काला दिन ...
 25 अक्टूबर 2018 का दिन हमारे परिवार और कोसीर समाज के लिए काला दिन बनकर उभरा। आप अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारी निभा ही रहे थे कि अचानक आपकी तबीयत बिगड़ गई। हमें रायपुर ले जाना पड़ा। 29 अक्टूबर 2018 की रात 7 बजे डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल, रायपुर में आपने अंतिम सांस ली। 25 अक्टूबर के बाद आपने आँखें नहीं खोलीं, मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सका। मात्र 56 वर्ष की अल्पायु में आप हमसे रूठ गए। आज 29 अक्टूबर 2026 को आपकी 8वीं पुण्यतिथि है। आदा साल बनी जाए, आपको कमी आज भी वैसी ही है। खेत आज भी आपको पुकारते हैं, घर की देहरी आज भी आपको राह देखती है, और समाज आज भी आपके जैसे सरल, सशक्त नेतृत्व को याद करता है। आप मेरे लिए पिता ही नहीं, मेरे पहले गुरु, मेरे पहले मित्र और मेरे जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। समाज के लिए आप एक ऐसे किसान पुत्र थे जिन्होंने बिना डिग्री के भी जीवन की सबसे बड़ी युगविासिंटी से शिक्षा लेकर सबको जीना सिखाया। **बाबूजी, आपको 8वीं पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि, शत-शत नमन।**



दौरा टला,सौगात नहीं! चक्रवात के चलते वर्चुअल जुड़े सीएम साय,सूरजपुर को 232 करोड़ से अधिक के विकास कार्य

जल संचय जनभागीदारी अभियान में सूरजपुर प्रदेश में प्रथम और देश में चौथे स्थान पर,जल संरक्षण के 2,212 कार्यों पर खर्च होंगे 130.56 करोड़

मौसम ने बदला मुख्यमंत्री का कार्यक्रम,प्रेमनगर में वर्चुअल हुआ विकास का महाआयोजन

सूरजपुर,28 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में प्रस्तावित दौरा अचानक चक्रवात 'अर्नब' के कारण बनी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के चलते टालना पड़ा,मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां की गई थीं और उनके कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, हालांकि,पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को निरस्त करने के बजाय तय समय पर वर्चुअल माध्यम से संपन्न कराया गया,मुख्यमंत्री रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल हुए और सूरजपुर जिले को 232 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी,इस दौरान उन्होंने 24 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से पूर्ण 63 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 208 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत के 54 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया,साथ ही प्रेमनगर नगर पंचायत के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपये के अतिरिक्त विकास कार्यों की घोषणा की,मुख्यमंत्री के प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाने के बावजूद विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमिपूजन और घोषणाओं का कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार आयोजित किया गया,मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि सरगुजा और बस्तर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाओं को साकार करना राज्य सरकार का संकल्प है,सड़क, शिक्षा,स्वास्थ्य,सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर योजनाओं का लाभ

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

प्रेमनगर को डोम,इंडोर स्टेडियम और सड़क की सौगात- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेमनगर नगर पंचायत के विकास के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं,मंगल भवन के पास डोम निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये, इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए 50 लाख रुपये और वाई क्रमांक 10,11 एवं 12 से विश्रामगृह तक लगभग दो किलोमीटर बीटी सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये देने की घोषणा की गई,इन तीनों घोषणाओं की कुल राशि 2 करोड़ 70 लाख रुपये है, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई मांगों के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी,इन घोषणाओं से नगर में सार्वजनिक आयोजनों के लिए सुविधा विकसित करने,खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और सड़क संपर्क बेहतर बनाने की उम्मीद है,उन्होंने कहा कि सूरजपुर जिले के लिए एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन प्रगति को नई गति देने वाला कदम है। इन कार्यों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे,मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित नहीं हो पाने पर क्षेत्रवासियों से खेद व्यक्त किया,उन्होंने कहा कि वे प्रेमनगर के लोगों से प्रत्यक्ष मुलाकात करने के इच्छुक थे,लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका,उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन की सरहना भी की।

जल संचय अभियान में सूरजपुर प्रदेश में प्रथम, देश में चौथे स्थान पर-कार्यक्रम में सूरजपुर जिले की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने जल संचय

किसानों की समृद्धि और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं,उन्होंने राज्य में किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी,धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और किसानों को उनकी उपज बेचने में सुविधा देने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया,उनके अनुसार, प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्रों को स्वीकृति दी गई है,जिससे किसानों को खरीदी केंद्रों तक पहुंचने और प्रतीक्षा करने में होने वाली परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी,मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार जरूरी है, प्रदेश में सिंचाई से जुड़े 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों को स्वीकृति दी गई है,इसके अलावा पुरानी सिंचाई योजनाओं की मरम्मत और जोंगोंद्वारा के लिए 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, इन कार्यों से नहरों,बांधों के गेट और अन्य सिंचाई संरचनाओं में सुधार कर किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

जनभागीदारी अभियान में जिले के प्रदेश में प्रथम और देश में चौथे स्थान पर रहने पर नागरिकों,कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीम को बधाई दी,उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जनभागीदारी,जागरूकता और प्रशासन के समर्पित प्रयासों का उद्घाटन है,मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते वर्षा चक्र,गिरते भूजल स्तर और पेयजल की बढ़ती जरूरतों के बीच जल संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है,वर्षा जल का संचयन,पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग की जिम्मेदारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति की है,सूरजपुर जिले में इस दिशा में किए गए प्रयास दूसरे जिलों के लिए भी प्रेरणादायक हो सकते हैं, उन्होंने बताया कि जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित अयोसंरचना विकास के 2,212 कार्यों पर लगभग 130 करोड़ 56 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे,इन कार्यों से वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देने,भूजल स्तर सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलने की उम्मीद है,मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

है और वन संपदा स्थानीय आजीविका का मजबूत आधार बन सकती है।

बस्तर और सरगुजा में विकास की नई संभावनाएं-मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का वातावरण बनाने की दिशा में काम हो रहा है, जिन क्षेत्रों में पहले विकास कार्यों में बाधाएं आती थीं,वहां सड़क, बिजली, पानी,आवास और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है,उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसे वनांचलों में पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं,प्राकृतिक सूर्यरता,सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पर्यटन स्थलों को पहचान दिलाने से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

शासकीय सेवाओं को घर बैठे उपलब्ध कराने का प्रयास-मुख्यमंत्री ने सुशासन का उल्लेख करते हुए कहा कि आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें,यह सरकार का प्रयास है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक शिकायतें दर्ज कर सकते हैं,वर्षा,सेवा सेतु के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है,उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से शासकीय सेवाओं के साथ बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रयास है,जिससे ग्रामीणों को जरूरी कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने अंजोर विजन 2047 का उल्लेख करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में आम नागरिकों की सहभागिता का आह्वान किया।

कृषि मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी रखे विचार-कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरगुजा संभाग सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिली है,उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से ग्राम पंचायतों की जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकता तय कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया,उन्होंने कहा कि सूरजपुर जिला प्राकृतिक संसाधनों और विकास की संभावनाओं से समृद्ध है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाओं,किसानों, गरीब परिवारों और जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है,महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक संवल दे रही है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाना प्रदेश की समृद्धि के लिए आवश्यक है, कार्यक्रम में सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक गोमती साय, भरत सिंह सिसोदिया,प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी,विधायक शकुन्तला पोते, जिला पंचायत अध्यक्ष चंदमणि पैकार,उपाध्यक्ष रेखा राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिकारियों में सरगुजा आयुक्त नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक झा,कलेक्टर रेंना जमील,पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल और जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए,इस तरह प्रतिकूल मौसम के कारण मुख्यमंत्री का प्रस्तावित सूरजपुर दौरा भले ही स्थगित करना पड़ा, लेकिन वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में जिले के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और नई घोषणाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हुईं।

बाइक से गिरे युवकों ने मदद करने वाले पर ईंट से किया हमला

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाषनगर, दुर्गावाड़ी निवासी एक युवक के साथ बीते 20 अक्टूबर को रात करीब 12 बजे मोटरसाइकल सवारों के द्वारा की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक,अमित मंडल अपने भांजा राजा के साथ मंदिर से आकर खाना खा रहा था। उसी समय बाहर मोटरसाइकिल से किसी के गिरने की आवाज सुनकर दोनों बाहर निकले तो दो व्यक्ति बाइक से गिरे हुए थे। दोनों को उठाने के बाद अमित ने पूछा कहाँ जा रहे हो। इस बात पर दोनों नाराज हो गए और गालीगलौज करते हुए तुम पूछने वाले कौन होते हो कहने लगे। बाइक सवारों ने कहा कि वे अमित मंडल के रूम में रहते हैं। बाइक सवारों ने जिस प्रकार उसका नाम लिया तो सड़क की स्थिति बनी और पूछा कि अमित मंडल कैसा दिखता है। इस पर दोनों आक्रोश में आ गए और गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुए हथ-मुक्का से मारपीट करने लगे। इस दौरान भांजा राजा बीच-बचाव करने आया तो उस पर भी ईंट से हमला कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी मुकेश मंडल आया और विवाद शांत कराया। बाद में दोनों ने अपना नाम उत्तम सोनी और महात्मा निवासी बीरीपारा अंबिकापुर बताया। मारपीट में दोनों को गले और सीने में चोट आई है। पुलिस मामले में अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है।

गुटखा नहीं देने पर बहन को लेने जा रहे युवक से मारपीट

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना अंतर्गत नवापारा में बहन को लेने जा रहे मजदूर के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक,गंगापुर में सुभाष चैक के पास रहने वाला प्रिंस डेविड बरवा टैट में मजदूर करता है। 27 अक्टूबर की शाम 4 बजे के लगभग वह स्कूटी वाहन से अपनी बहन को लेने सेंट जेवियर स्कूल नवापारा जा रहा था। इस दौरान नवापारा चर्च मैदान के पास एक व्यक्ति मिला जो बोला कहाँ जा रहे हो,जिस पर उसने बहन को लेने जा रहा हूँ कहा। उक्त युवक ने स्कूटी सवार को गुटखा खिलाने के लिए कहा,तो वह बोला कि मेरे पास गुटखा नहीं है। इसी बात से नाराज होकर वह गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का,डण्डा से मारपीट करके भाग गया। बहन को स्कूल से घर लेकर आने के बाद वह नवापारा में रहने वाले दोस्त को इसकी जानकारी दिया तो वह इंस्टाग्राम में एक फोटो दिखाया,जो मारपीट करने वाला नवापारा निवासी प्रवण पंडित था।

अंडर-14 क्रिकेट में सरगुजा का धमाकेदार आगाज,दुर्ग को 10 विकेट से हराया

सनी ओझा और तोसिक मानिकपुरी ने झटके 3-3 विकेट,गगन बोस व चिराग राजवाड़े ने दिलाई

आसान जीत,कोच अलंकार तिवारी ने बीसीसीआई लेवल-0 कोर्स में हासिल किए 97 प्रतिशत अंक

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता में सरगुजा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले मुकाबले में दुर्ग को 10 विकेट से करारी हारिस्त दी। भिलाई के सेक्टर-1 मैदान पर खेले गए मुकाबले में सरगुजा के गेंदबाजों ने दुर्ग की टीम को महज 69 रनों पर समेट दिया। इसके बाद सलामी बल्लेबाज गगन बोस और चिराग राजवाड़े ने बिना विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर टीम को शानदार जीत दिलाई। टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने उतरी सरगुजा की टीम ने शुरुआत से ही दुर्ग के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। तेज गेंदबाज प्रिंस कुशवाहा ने शुरुआती ओवरों में विकेट लेकर टीम को अच्छे शुरुआत दिलाई। इसके बाद स्वास्तिक केसरी और सनी ओझा ने कसी हुई गेंदबाजी से विपक्षी टीम को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।



सनी ओझा और तोसिक मानिकपुरी ने तीन-तीन विकेट लेकर दुर्ग की बल्लेबाजी को कमर तोड़ दी। सरगुजा के गेंदबाजों के संयुक्त प्रदर्शन के सामने दुर्ग की पूरी टीम 30 ओवर में 69 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।

गगन और चिराग ने बिना विकेट गंवाए दिलाई जीत : 70 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी सरगुजा की टीम ने आक्रमक और संयमित बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। गगन बोस और चिराग राजवाड़े ने शानदार तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए 33-33 रन बनाए

सर्टिफिकेशन कोर्स में 97 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। जारी परिणाम के अनुसार, उन्होंने संयुक्त रूप से सर्वाधिक अंक प्राप्त किए और लेवल-1 कोर्स के लिए पात्रता हासिल की है। अलंकार तिवारी पिछले दो वर्षों से युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

वे बच्चों की तकनीक सुधारने, खेल की बारीकियां समझाने और मैदान पर बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। कोचिंग के क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाने के प्रयास में मिली यह सफलता उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे सरगुजा में क्रिकेट प्रशिक्षण की गुणवत्ता और युवा खिलाड़ियों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सरगुजा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंह देव ने अलंकार तिवारी की सफलता पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि वे पिछले दो वर्षों से बच्चों को प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण

योगदान दे रहे हैं। बीसीसीआई के कोर्स में 97 प्रतिशत अंक हासिल करना पूरे संघ के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अलंकार अपने ज्ञान और अनुभव से युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मदद करते रहेंगे। संघ के सचिव विनीत जायसवाल ने भी अलंकार तिवारी को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि को सराहनीय बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अलंकार आगामी स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सरगुजा में क्रिकेट के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। वहीं, संघ के कोषाध्यक्ष शैलू सिंह ने कहा कि सरगुजा की अंडर-14 टीम की शानदार जीत और कोच अलंकार तिवारी की बीसीसीआई लेवल-0 कोर्स में 97 प्रतिशत अंकों के साथ सफलता पूरे संघ के लिए गर्व की बात है। उन्होंने टीम के खिलाड़ियों और कोच अलंकार तिवारी को बधाई देते हुए आगामी मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।

शराब पीकर ई-रिक्शा चलाना पड़ा महंगा,न्यायालय ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

शराब पीकर वाहन चलाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे मामलों पर सख्ती बरतते हुए यातायात पुलिस ने शराब के नशे में ई-रिक्शा चलाने

वाले एक चालक के खिलाफ कार्रवाई की। मामले को न्यायालय में पेश किए जाने पर चालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। पुलिस के अनुसार, यातायात शाखा की टीम वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान ई-रिक्शा क्रमांक CG15EK3063 को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम सुधीर दुबे (42), पिता सुरेश दुबे, निवासी

बौरीपारा, थाना कोतवाली, अंबिकापुर बताया। जांच के दौरान चालक के शराब के नशे में होने का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई। शराब का सेवन कर वाहन चलाने के मामले में यातायात पुलिस ने चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद मामला न्यायालय के

समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां चालक को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यातायात पुलिस द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।



विकास पुरुष लरंग साय की प्रतिमा का अनावरण,बलरामपुर को 202 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से किया अनावरण, कुपोषण से लड़ने 967 बच्चों के लिए ‘बालभोग’ कार्यक्रम शुरू

—संवाददाता—
बलरामपुर,28 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

अविभाजित सरगुजा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और आदिवासी समाज के प्रमुख नेताओं में शुमार स्वर्गीय लरंग साय की स्मृति को चिरस्थायी बनाने की दिशा में उनके पैतृक ग्राम चिरई में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम चिरई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। इस अवसर पर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले को 202 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत के 2009 विकास कार्यों की सौगात मिली। कार्यक्रम में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन के साथ कुपोषण मुक्ति के लिए ‘बालभोग’ कार्यक्रम को शुरुआत भी की गई।

सादगी,ईमानदारी और जनसेवा के प्रतीक थे लरंग साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय लरंग साय को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन सादगी,ईमानदारी और स्पष्टवादिता का उदाहरण रहा है। एक साधारण शिक्षक से केंद्रीय मंत्री तक का उनका सफर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। आदिवासी समाज के उत्थान



और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए उनके योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे जननेताओं की स्मृतियां समाज को सेवा और समर्पण की राह दिखाती हैं। प्रतिमा अनावरण के साथ मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए तीन महत्वपूर्ण

967 कुपोषित बच्चों को मिलेगा पोष्टिक लड्डू

कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियों में महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल पर शुरू किया गया ‘बालभोग’ कार्यक्रम भी रहा। इसका उद्देश्य शंकरगढ़ विकासखंड में कुपोषण की समस्या को कम करना और बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराना है। योजना के तहत क्षेत्र के 967 कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन 30 ग्राम पोष्टिक लड्डू दिए जाएंगे। श्रीअन्न यानी मिलेट,रागी और सूखे मेवों से तैयार इन लड्डूओं के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी भी की जाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को भी मिलेट आधारित उत्पाद उपलब्ध कराने की पहल की गई है।

घोषणाएं भी कीं। इनमें शंकरगढ़ में विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार,ग्राम चांदों में सामुदायिक भवन का निर्माण तथा ग्राम चिरई में स्वर्गीय लरंग साय की प्रतिमा के समीप भव्य स्मृति द्वार का निर्माण शामिल है। इन कार्यों से क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और स्वर्गीय लरंग साय की स्मृति को संरक्षित करने की उम्मीद है।

2009 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन : मुख्यमंत्री द्वारा दी गई विकास कार्यों की सौगात में 156 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत के 1863 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास तथा 45 करोड़ 97 लाख रुपये के 146 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इन कार्यों से जिले में सड़क, पुल, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा और ग्रामीण

आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। भूमिपूजन एवं शिलान्यास के प्रमुख कार्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 71 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से बनने वाली तीन सड़कें, कुसमी क्षेत्र में 26 करोड़ 15 लाख रुपये की लागत से पांच पुलों का निर्माण तथा जिला चिकित्सालय में 4 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से सीटी स्कैन मशीन स्थापित करने का कार्य शामिल है। इसके अलावा वीबी-जी राम जी योजना के तहत प्रस्तावित कार्य भी इस सूची में शामिल हैं। वहीं, लोकार्पित कार्यों में 15 एकल ग्राम नल-जल योजनाएं,मनरेगा के तहत निर्मित 97 चेकडैम, नए छात्रावास, उप स्वास्थ्य केंद्र और महतारी सदन प्रमुख हैं। इन सुविधाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता,

सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाओं और महिलाओं की सामुदायिक गतिविधियों को मजबूती मिलने की संभावना है।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रही मौजूदगी

कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेनाम, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा,लरंग साय सेवा समिति के अध्यक्ष राम लखन सिंह पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरामुनी निंजुज, कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

स्वर्गीय लरंग साय की प्रतिमा का अनावरण, उनके नाम पर स्मृति द्वार की घोषणा और जिले को मिली विकास कार्यों की सौगात ने कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया। वहीं, ‘बालभोग’ कार्यक्रम से कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने की पहल को जिले में बाल स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब इन योजनाओं की वास्तविक सफलता उनके समयबद्ध क्रियान्वयन, सुविधाओं की गुणवत्ता और लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचने पर निर्भर करेगी।

गांधीनगर पुलिस ने दो बाइक चोरी के मामलों का किया खुलासा,आरोपी गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से करीब एक लाख रुपये कीमत की दो मोटरसाइकिलें बरामद

संवाददाता—
अम्बिकापुर,28 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के दो मामलों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई दो मोटरसाइकिलें,जिनकी कुल कीमत करीब एक लाख रुपये बताई गई है,बरामद की हैं। दोनों घटनाओं में अलग-अलग अपराध दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस के अनुसार, पहले मामले में बड़नीझरिया निवासी इन्द्रकमल जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 अक्टूबर 2026 की रात उनकी हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG15DV1607 घर के सामने से चोरी हो गई। शिकायत पर गांधीनगर थाने में अपराध क्रमांक 646/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(बी) और 303(2) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। वहीं,दूसरे मामले में छिन्नामा निवासी राजकुमार यादव ने शिकायत की थी कि 20 अक्टूबर 2026 को भावानपुर शासकीय हाई स्कूल के बगल से उनकी पत्नी के नाम



पर दर्ज मोटरसाइकिल क्रमांक CG30G-0529 चोरी हो गई। पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 687/26 के तहत बीएनएस की धारा 303(2) में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। दोनों मामलों की जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही छोटे लाल (28),पिता रयाम लाल,निवासी मंजीरा फुलकुंवर पार,थाना जयनगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने दोनों स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर दोनों चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर जब्त की गईं।

म्यूल बैंक खातों से 14.17 लाख की साइबर टगी,खाता खुलवाने वाला आरोपी गिरफ्तार

प्रति खाता एक हजार रुपये लेकर खुलवाता था खाते,पंजाब नेशनल बैंक के खातों का टगी के लेन-देन में इस्तेमाल,अन्य सहयोगियों की तलाश जारी

संवाददाता—
अम्बिकापुर,28 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

साइबर टगी के लिए दूसरों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर उनका इस्तेमाल करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने सूरजपुर जिले के एक 54 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रति खाता एक हजार रुपये लेकर पंजाब नेशनल बैंक में खाते खुलवाता था और उन्हें मोबाइल नंबरों से लिंक करवाता था। इन खातों का इस्तेमाल विभिन्न राज्यों में लोगों से 14 लाख 17 हजार 49 रुपये की ऑनलाइन टगी से जुड़े लेन-देन में किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बैंक पासबुक की छायाप्रतियां जब्त की हैं। मामले में अन्य मोबाइल धारकों और सहयोगियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर म्यूल बैंक खातों और फर्जी मोबाइल नंबर जारी करने वाले पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस)



संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। दस्तावेजों की जांच में संबंधित बैंक खाते के विरुद्ध साइबर अपराध पोर्टल पर विभिन्न राज्यों से ऑनलाइन शिकायतें दर्ज होने की जानकारी सामने आई। जांच में इन खातों का कथित तौर पर धोखाधड़ी की रकम प्राप्त करने और उसके लेन-देन में इस्तेमाल किया जाना पाया गया। इसके बाद कोतवाली

थाने में अपराध क्रमांक 761/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 317(4) और 3(5) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

फेसबुक पर हुई पहचान,खाते खुलवाने के बदले लेता था रकम : विवेचना के दौरान पुलिस ने संबंधित खाताधारकों के बयान दर्ज किए और सीतेश कुमार भारती, पिता स्वर्गीय त्रिलोक राम, निवासी द्वारिका नगर,लटोरी चौकी,जिला सूरजपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार,पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से उसकी एक व्यक्ति से पहचान हुई थी। इसके बाद वह प्रति खाता एक हजार रुपये लेकर अन्य लोगों के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक में खाते खुलवाने और उन्हें मोबाइल नंबरों से लिंक कराने का काम करने लगा। पुलिस का कहना है कि इन खातों का इस्तेमाल विभिन्न राज्यों में हुई ऑनलाइन टगी की रकम के लेन-देन के लिए किया गया। जांच के दौरान आरोपी द्वारा खाताधारकों के मूल दस्तावेज प्रस्तुत

नहीं किए जाने और अस्पष्ट छायाप्रतियां दिए जाने के मामले में साक्ष्य छिपाने से संबंधित तथ्य सामने आने पर प्रकरण में बीएनएस की धारा 238 भी जोड़ी गई। पुलिस ने बैंक पासबुक की छायाप्रतियां जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी : पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य मोबाइल नंबर धारकों,खातों के उपयोगकर्ताओं और सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कथित तौर पर खुलवाए गए बैंक खातों का इस्तेमाल किन-किन साइबर अपराधों में हुआ और टगी की रकम का लेन-देन किन माध्यमों से किया गया। इस कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, साइबर सेल टीम और आरक्षक जोधन पैकरा की भूमिका रही। पुलिस ने म्यूल बैंक खातों के जरिए होने वाले साइबर अपराधों पर कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

सरगुजा इलेवन की खिताबी मुकाबले में एंट्री,तपकरा को 3-0 से हराया



—संवाददाता—
अम्बिकापुर,28 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

नगर के गांधी स्टेडियम में खेला जा रही संभाग स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता-2026 के दूसरे सेमीफाइनल में सरगुजा इलेवन ने तपकरा को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब 29 अक्टूबर को खिताबी मुकाबले में सरगुजा इलेवन का सामना बलसेड़ी की टीम से होगा। बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल के पहले हाफ में दोनों टीमों ने अच्छे तालमेल के साथ खेलते हुए गोल करने के कई प्रयास किए,लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। दूसरे हाफ में सरगुजा इलेवन ने आक्रामक खेल दिखाया और एक गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली। मैच के अंतिम समय में टीम ने लगातार दो और गोल दागरक स्कोर 3-0 कर दिया। अंतिम: सरगुजा इलेवन ने मुकाबला अपने नाम कर फाइनल का टिकट पक्का किया। मैच में मुख्य अतिथि के रूप में थोक फल विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष सोनकर,सचिव जितेंद्र गुप्ता और जिला फुटबॉल संघ के संरक्षक जगजीत मिंज उपस्थित रहे। मैच में विलसन, सुरील,शिव,ललित किशोर और दिनेश तिकी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्य दीपक कुजूर, कमलेश किशोरा, अखिलानंद और मंगल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 29 अक्टूबर को सरगुजा इलेवन और बलसेड़ी के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी।

पैच रिपेयरिंग के नाम पर सड़क पर डामर की जगह जला ऑयल डालने का आरोप

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,28 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

शहर में सड़कों की मरम्मत और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। पुराने नगर निगम भवन से चौपाटी तक पैच रिपेयरिंग के नाम पर कराए गए सड़क कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा है। आरोप है कि रात के अंधेरे में डामर की जगह जला हुआ इंजन ऑयल डालकर सड़क की टायरिंग की गई। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाबा कार्तिक उरांव चौक के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन से पहले सड़क को दुरुस्त और मजबूत की कोशिश की गई थी। हालांकि,इस दौरान कराए गए कार्य की गुणवत्ता पर ही सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैच रिपेयरिंग के नाम पर सड़क की ऊपरी सतह को ठीक करने के बजाय औपचारिकता निभाई गई।

‘वोट चोर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे’ के नारों से गुंजा लुंझा तहसील कार्यालय किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा ने निकाली रैली,समान नागरिक संहिता के अभियान पर भी जताया विरोध,राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन...

संवाददाता—
लुंझा,28 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ किसान सभा तथा आदिवासी एकता महासभा ने बुधवार को लुंझा तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। दोनों संगठनों की तहसील समितियों के संयुक्त नेतृत्व में रैली,धरना और आमसभा आयोजित की गई। इस दौरान ‘वोट चोर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे’ और ‘समान नागरिक संहिता की नौटंकी बंद करो’ जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। किसान सभा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आंदोलन में शामिल कार्यकर्ता लुंझा के निकट ग्राम बहेराडीह में एकत्रित हुए। हाथों में लाल झंडे लेकर इंकलाबी नारे लगाते हुए वे जुलूस के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां आयोजित आमसभा में किसान एवं आदिवासी नेताओं ने अपनी मांगें रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की।

आयोजकों के मुताबिक, अचानक मौसम खराब होने और बारिश के कारण अपेक्षा से कम लोग जुटें,लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोगों ने शासन-प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई।



मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूचियों में कथित हेराफेरी और चुनाव आयोग के संचालन में मनमानी के आरोप लगाए। संगठन का दावा है कि आयोग में अन्य दो चुनाव आयुक्तों के मतों की अनदेखी कर एकराफा निर्णय लिए गए, जिसके कारण लगभग 13 करोड़ मतदाता मतदान से वंचित रह गए। ये आरोप किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा की ओर से ज्ञापन में लगाए गए हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि ज्ञानेश कुमार स्वयं इस्तीफा दें। ऐसा नहीं होने पर राष्ट्रपति से उन्हें पद से हटाने और मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों के मामले में आपराधिक प्रकरण चलाने की मांग की गई। संगठनों ने कथित तौर पर दूषित मतदाता सूचियों के आधार पर हुए चुनावों को रद्द करने, उनसे गठित विधानसभाओं को भंग करने और संबंधित सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी रखी।

समान नागरिक संहिता के अभियान पर उठाए सवाल : प्रदर्शनकारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की समान नागरिक संहिता संबंधी पहल पर भी

विरोध जताया। ज्ञापन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न धर्मों,जातियों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के लोग रहते हैं। विशेष रूप से आदिवासी समुदायों



बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने जताई नाराजगी

आयोजकों के अनुसार,आंदोलन में लुंझा तहसील क्षेत्र के दूर-दराज के गांवों से भी लोग शामिल हुए। खराब मौसम और बारिश के कारण उपस्थिति प्रभावित हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। आमसभा में वक्ताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया,मताधिकार और आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए। यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ किसान सभा की सरगुजा जिला समिति और आदिवासी एकता महासभा की लुंझा तहसील समितियों के संयुक्त आह्वान पर किया गया। प्रेस विज्ञप्ति छत्तीसगढ़ किसान सभा की सरगुजा जिला समिति के उपाध्यक्ष सीपी शुक्ला की ओर से जारी की गई।

की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक पहचान है। ऐसे में किसी एक संस्कृति या जीवन-पद्धति को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

संगठनों ने इसे संविधान प्रदत्त अधिकारों और सांस्कृतिक स्वतंत्रता से जुड़ा विषय बताते हुए राज्य सरकार से

समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद तत्काल बंद करने की मांग की। राष्ट्रपति से भी राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश देने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि आदिवासी समुदायों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों की परंपराओं और जीवन-पद्धति में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निधन

अम्बिकापुर,28 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। मेडिकल कालेज चिकित्सालय के रिटायर्ड पूर्व एमएस डॉ. घनश्याम सिंह का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को शहर के शंकरघाट स्थित मुक्तिधाम में किया गया।

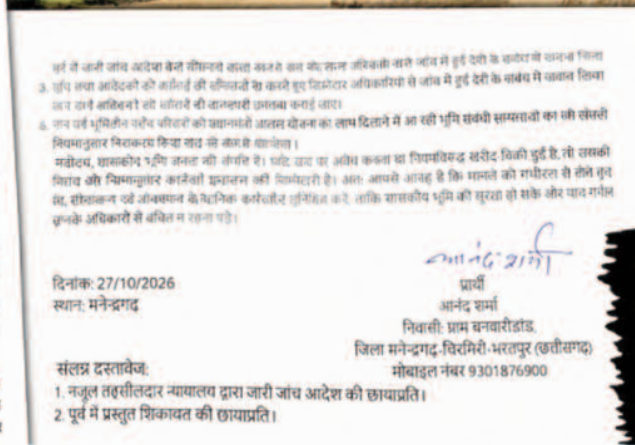
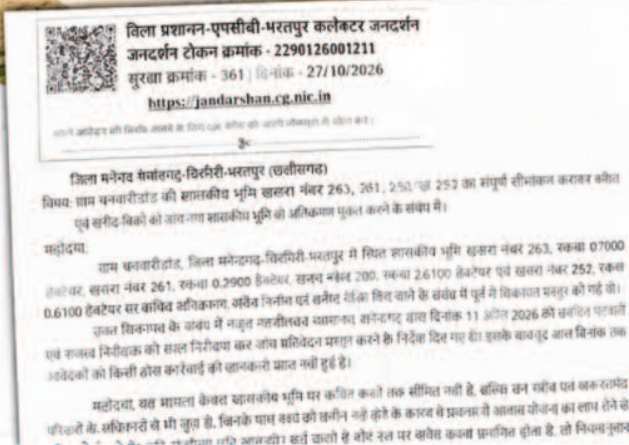


डॉ. घनश्याम सिंह

चनवारीडांड की शासकीय भूमि का मामला 4.21 हेक्टेयर का विवाद दूसरी बार जनदर्शन में शिकायत आखिर कब होगी कार्रवाई? नजूल तहसीलदार के जांच आदेश के बावजूद कार्रवाई पर सवाल



**आनंद शर्मा ने
दूसरी बार जनदर्शन में
प्रस्तुत किया आवेदन**



- चार खसरों का सीमांकन कराने की मांग
- कथित अतिक्रमण, निर्माण और खरीद-बिक्री की जांच की मांग
- 11 अप्रैल 2026 के जांच आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं?
- भूमिहीन गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग

4.21 हेक्टेयर शासकीय भूमि का मामला में दूसरी बार जनदर्शन में शिकायत, आखिर कब होगी कार्रवाई?

चनवारीडांड के चार खसरों के सीमांकन और कथित अतिक्रमण व खरीद-बिक्री की जांच की मांग, 11 अप्रैल के जांच आदेश के पालन पर उठा सवाल

**आनंद शर्मा ने कलेक्टर
जनदर्शन में सौंपा आवेदन,
भूमिहीन परिवारों को
प्रधानमंत्री आवास योजना
का लाभ दिलाने की भी मांग**

**नजूल तहसीलदार के जांच
आदेश के छह महीने बाद भी
कार्रवाई की स्थिति पर सवाल**

**आनंद शर्मा ने चार खसरों के
सीमांकन, कथित अतिक्रमण
और खरीद-बिक्री की निष्पक्ष
जांच की उठाई मांग**

-संवाददाता-
एमसीबी, 28 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

ग्राम चनवारीडांड की 4.21 हेक्टेयर शासकीय भूमि से जुड़ा मामला अब जिला प्रशासन के जनदर्शन में दूसरी बार पहुंच गया है, कथित अतिक्रमण, निर्माण और खरीद-बिक्री की जांच

की मांग को लेकर आनंद शर्मा ने 27 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर के जनदर्शन में आवेदन प्रस्तुत किया है, शिकायतकर्ता ने चार खसरों की भूमि का संयुक्त सीमांकन कराने, राजस्व अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान करने तथा अनियमितता प्रमाणित होने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नजूल तहसीलदार न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ द्वारा 11 अप्रैल 2026 को संबंधित पटवारी और राजस्व निरीक्षक को स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाने का उल्लेख शिकायत में है, तो अब तक जांच की स्थिति क्या है? क्या मौके का निरीक्षण किया गया, क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ और यदि कार्रवाई लंबित है तो इसके पीछे क्या कारण हैं? शिकायतकर्ता ने इन्हें बिंदुओं पर प्रशासन से स्पष्ट जवाब और कार्रवाई की मांग की है।

**चार खसरों की 4.2100 हेक्टेयर
भूमि जांच के दायरे में**

आनंद शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन में ग्राम चनवारीडांड स्थित चार खसरों की शासकीय भूमि का उल्लेख किया गया है, इनमें खसरा नंबर 263, रकबा 0.7000 हेक्टेयर, खसरा नंबर 261, रकबा 0.2900 हेक्टेयर, खसरा

नंबर 250, रकबा 2.6100 हेक्टेयर और खसरा नंबर 252, रकबा 0.6100 हेक्टेयर शामिल हैं। इन चारों खसरों का कुल रकबा

दूसरी बार जनदर्शन में आवेदन, अब जवाबदेही की बारी

चनवारीडांड की 4.21 हेक्टेयर शासकीय भूमि से जुड़े इस मामले में अब निगाह जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है, शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन के साथ पूर्व में जारी जांच आदेश और पहले प्रस्तुत शिकायत की प्रतियां संलग्न किए जाने का उल्लेख किया है, इससे प्रशासन के समक्ष पूर्व शिकायत और वर्तमान मांगों की समीक्षा करने का आधार उपलब्ध है, अब अहम सवाल यह है कि संबंधित राजस्व अधिकारियों ने जांच आदेश के बाद क्या कदम उठाए? क्या चारों खसरों का सीमांकन हुआ? क्या मौके पर निर्माण और कब्जे की स्थिति दर्ज की गई? और क्या कथित खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों और जिला प्रशासन के पक्ष से सामने आना बाकी है, पिछले आवेदन में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और किसी व्यक्ति की संलिप्तता को प्रमाणित नहीं माना जा सकता, शासकीय भूमि की सुरक्षा और राजस्व रिकॉर्ड की पारदर्शिता जनहित से जुड़े विषय हैं, ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच के साथ उसकी प्रगति और निष्कर्ष स्पष्ट करना भी जरूरी है, अब देखा होगा कि दूसरी बार जनदर्शन में पहुंचे इस आवेदन पर प्रशासन कब तक जांच की स्थिति स्पष्ट करता है और नियमानुसार क्या कार्रवाई करता है।

4.2100 हेक्टेयर है, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित भूमि पर कथित अतिक्रमण, निर्माण और खरीद-बिक्री की आशंका को देखते हुए इसकी विस्तृत जांच जरूरी है, आवेदक ने राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर चारों खसरों का निष्पक्ष सीमांकन कराने की मांग की है, ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति और उसके वर्तमान उपयोग का पता चल सके, हालांकि, शासकीय भूमि पर

अतिक्रमण अथवा अवैध खरीद-बिक्री की पुष्टि अभी जांच का विषय है, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष राजस्व अभिलेखों, सीमांकन

आवेदन के अनुसार, इस मामले में नजूल तहसीलदार न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ द्वारा 11 अप्रैल 2026 को संबंधित पटवारी और राजस्व निरीक्षक को स्थल निरीक्षण कर जांच

और सक्षम अधिकारियों की जांच के आधार पर ही निकाला जा सकता है।

**11 अप्रैल के जांच आदेश के
पालन पर उठे सवाल**

आवेदन के अनुसार, इस मामले में नजूल तहसीलदार न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ द्वारा 11 अप्रैल 2026 को संबंधित पटवारी और राजस्व निरीक्षक को स्थल निरीक्षण कर जांच

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, शिकायतकर्ता का कहना है कि इसके बावजूद उन्हें अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली है, इसी कारण उन्होंने 27 अक्टूबर को दूसरी बार जनदर्शन में आवेदन देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की, अब प्रशासन के सामने यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि पूर्व में जारी निर्देशों का पालन हुआ या नहीं, यदि जांच पूरी हो चुकी है तो प्रतिवेदन में क्या निष्कर्ष सामने आए? यदि जांच नहीं हुई है, तो देरी के कारण क्या है? यह मामला केवल शिकायत दर्ज होने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जांच के आदेश के बाद उसकी प्रगति और निष्कर्ष की जानकारी भी शिकायतकर्ता को मिलनी चाहिए, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे।

**निर्माण, कब्जे और खरीद-बिक्री के
दस्तावेजों की जांच की मांग**

शिकायत में आवेदक ने चारों खसरों की भूमि पर वर्तमान में किए गए निर्माण, कब्जे और उपयोग की स्थिति की विस्तृत जांच कराने का आग्रह किया है, साथ ही कथित खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर यह पता लगाने की मांग की गई है कि भूमि के संबंध में कोई लेन-देन हुआ है तो वह किन परिस्थितियों में और किन व्यक्तियों के बीच हुआ, आवेदन में यह भी

कहा गया है कि यदि जांच में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा प्रमाणित होता है, तो नियमानुसार अतिक्रमण हटाकर भूमि को शासकीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित किया जाए, वहीं, यदि कथित खरीद-बिक्री में अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, इन मांगों पर निर्णय लेने से पहले राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति और उपलब्ध दस्तावेजों का निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक होगा।

**प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र
हितग्राहियों का मुद्दा भी उठाया**

आनंद शर्मा ने अपने आवेदन में भूमिहीन और जरूरतमंद गरीब परिवारों का मुद्दा भी उठाया है, उनका कहना है कि जिन परिवारों के पास स्वयं की जमीन नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने में भूमि संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आवेदन में मांग की गई है कि पात्र एवं भूमिहीन गरीब परिवारों की भूमि संबंधी समस्याओं का नियमानुसार निराकरण किया जाए, ताकि वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें, हालांकि, इस मामले में कितने परिवार प्रभावित हैं और उनकी समस्याओं की वास्तविक स्थिति क्या है, यह संबंधित अभिलेखों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 29 बालिकाओं ने किया शैक्षणिक भ्रमण



**महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण
एवं शासकीय योजनाओं की दी
गई जानकारी, शिक्षा और
आत्मनिर्भरता के लिए किया प्रेरित**

-संवाददाता-
एमसीबी, 28 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं प्रशासनिक समझ विकसित करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब), जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (टी-सर्वग) की 29 बालिकाओं को विभिन्न शासकीय कार्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। कलेक्टर संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग

के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। भ्रमण के दौरान बालिकाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं बाल कल्याण समिति की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। संबंधित अधिकारियों ने महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सहायता के लिए संचालित व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन 181 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की उपयोगिता और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। इस अवसर पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, मिशन वास्तव्य, सॉन्सरशिप योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सशक्तिकरण तथा बाल विवाह की रोकथाम से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की रक्षा और जरूरतमंदों को

सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न शासकीय संस्थाएं कार्यरत हैं। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को शिक्षा के महत्व, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता, साइबर सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, स्वच्छता तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने, आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने और भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। बालिकाओं ने अधिकारियों से संवाद कर शासकीय सेवाओं एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। यह शैक्षणिक भ्रमण बालिकाओं के ज्ञावर्धन, व्यक्तिगत विकास एवं सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रही। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा स्वल्पाहार के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ।

दिशा समिति की बैठक में केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा; बालिका सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और हसदेव उद्गम के संरक्षण पर दिए निर्देश पेयजल आपूर्ति और प्रधानमंत्री सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करें : सांसद ज्योत्सना



-संवाददाता-
कोरिया, 28 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

लोकसभा क्षेत्र कोरबा की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने पेयजल आपूर्ति और प्रधानमंत्री सड़क योजना के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत के मंथन कक्ष में उनकी अध्यक्षता में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति 'दिशा' की बैठक में जिले में संचालित केन्द्रीय जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्रीमती रोकित्मा यादव ने योजनाओं के क्रियान्वयन और जिले की उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण दिया। सांसद श्रीमती महंत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में प्रधानमंत्री सड़क योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने इनके सुचारु क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सांसद ने बालिका विद्यालयों में शौचालय, पेयजल और चारदीवारी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत बताई। उन्होंने आवश्यक कार्यों के लिए एसईसीएल को प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए श्रीमती महंत ने दुर्घटनाप्रवण क्षेत्रों की पहचान कर वहां सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा। भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तालाबों और नदियों के पुनरुद्धार तथा जल संरक्षण पर केंद्रित कार्य करने के निर्देश दिए। हसदेव नदी के मूल उद्गम को संरक्षित रखते हुए उद्गम स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की भी कहा। बैठक में कलेक्टर श्रीमती रोकित्मा यादव ने

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों, बिहान के माध्यम से महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की पहल और आवास योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निर्माणधीन 200 बिस्तर वाले अस्पताल का कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। कलेक्टर ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं, कृषि, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रगति भी प्रस्तुत की। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित राम पैकरा, पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेन्द्र श्रीवास्तव, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर अध्यक्ष श्री उदय सिंह सहित अन्य नामित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।



राजीव गुप्ता
कांग्रेस नेता

“एसईसीएल मैदान को आम लोगों के लिए खोलना चाहिए, यह खेलकूद और जनसुविधाओं के लिए बेहतर विकल्प है।”



एसईसीएल मैदान
आम लोगों के लिए खोलने की मांग



प्रस्तावित स्टेडियम (कल्पना चित्र)
बंद हैचरी की जमीन पर समतलीकरण कर बनाया जा सकता है आधुनिक स्टेडियम



मुख्य मार्ग से प्रवेश
प्रेम बाग कॉलोनी (पीछे का रास्ता)
बंद सरकारी हैचरी की जमीन
हैचरी का मुख्य मार्ग
मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता



सीए प्रशांत गुप्ता
भाजपा (अध्यक्ष पद के दावेदार)

“बंद हैचरी की जमीन पर शहर के लिए एक बड़े स्टेडियम की संभावना बन सकती है! यह जगह हर तरह से उपयुक्त है।”

अब देखना है...
यह प्रस्ताव चुनावी घोषणा बनेगा या बैकुंठपुर को मिलेगा सच में अपना स्टेडियम?

शहर के बीचों-बीच मुख्य मार्ग के पास

चारों तरफ से पहुंच के विकल्प (मुख्य मार्ग, हैचरी मार्ग, प्रेम बाग के पीछे, मंदिर मार्ग)

बड़े आयोजनों के लिए पार्किंग की संभावना

खेल, जिम, टहलने और जनसुविधाओं के लिए उपयुक्त

पुलिस लाइन, नगर पालिका और शहर के प्रमुख हिस्सों के पास

बैकुंठपुर में मैदान की लड़ाई ने पकड़ा जोर, दैनिक घटती-घटना की खबर के बाद कांग्रेस-भाजपा नेताओं ने खोले विकल्प

बैकुंठपुर को अपना स्टेडियम देने की पहल? बंद हैचरी की जमीन पर प्रशांत गुप्ता का प्रस्ताव,एसईसीएल मैदान पर भी मंथन

मिनी स्टेडियम पर आयोजनों का दबाव,अब हैचरी की जमीन पर स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव!

नगरपालिका चुनाव में गरमाया खेल मैदान का मुद्दा, कांग्रेस ने एसईसीएल तो भाजपा नेता ने हैचरी की जमीन पर जताई संभावना

आयोजनों से घिरा मिनी स्टेडियम,स्थायी खेल मैदान के लिए एसईसीएल ग्राउंड और हैचरी की जमीन पर नजर

जब शहर में जमीन है,तो स्टेडियम क्यों नहीं? बैकुंठपुर में एसईसीएल मैदान और बंद हैचरी पर उठी चर्चा

मिनी स्टेडियम में आयोजनों के दबाव के बीच राजीव गुप्ता ने एसईसीएल मैदान को आम लोगों के लिए खोलने की उठाई मांग

हैचरी की जमीन पर समतलीकरण कर स्टेडियम बनाने और कई दिशाओं से पहुंच मार्ग विकसित करने का सुझाव

कांग्रेस नेता राजीव गुप्ता ने एसईसीएल मैदान आम लोगों के लिए खोलने की रखी मांग, भाजपा के सीए प्रशांत गुप्ता ने भी इसी मैदान को बताया आयोजन का विकल्प

30 हजार की आबादी वाले जिला मुख्यालय में स्थायी खेल मैदान की जरूरत पर सवाल, बंद पड़ी हैचरी की जमीन पर भी हो सकता है विचार

बैकुंठपुर,28 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। शहर के बच्चों और युवाओं को खेलने के लिए पर्याप्त मैदान मिले, नागरिकों को सुबह-शाम टहलने की सुविधा हो और बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए स्कूल परिसर पर निर्भरता कम हो बैकुंठपुर में अब यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है, रामानुज मिनी स्टेडियम में लगातार होने वाले आयोजनों और विद्यार्थियों की खेल गतिविधियों पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर दैनिक घटती घटना में खबर प्रकाशित होने के बाद मैदान की समस्या पर बहस तेज हुई है, कांग्रेस से लेकर भाजपा तक,नेताओं के सामने अब सवाल है कि शहर के लिए वैकल्पिक मैदान कहाँ हो और उसे आम जनता के उपयोग के योग्य कैसे बनाया जाए।

इस बहस में कांग्रेस नेता राजीव गुप्ता ने एसईसीएल ऑफिसर्स कॉलोनी के भीतर स्थित मैदान को विकसित कर शहरवासियों के लिए



बैकुंठपुर को मिलेगा अपना स्टेडियम? बंद हैचरी की जमीन पर प्रशांत गुप्ता ने सुझाया नया विकल्प

खोलने का सुझाव दिया है, वहीं,भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार बताए जा रहे सीए प्रशांत गुप्ता ने भी एसईसीएल मैदान को विभिन्न शासकीय,अशासकीय और निजी आयोजनों के लिए संभावित विकल्प बताया है, इसके अलावा बंद पड़ी हैचरी की जमीन को भी एक संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है,अब मुद्दा केवल मैदान की कमी का नहीं, बल्कि शहर के सार्वजनिक स्थलों की उपलब्धता,उनके रखरखाव,इस्तेमाल की अनुमति और भविष्य की योजना का भी है,सवाल यह है कि क्या आगामी नगर पालिका चुनाव में खेल मैदान का मुद्दा केवल बयानों तक सीमित रहेगा,या प्रत्यक्षी इसके लिए ठोस कार्ययोजना भी सामने रखेंगे?

स्कूल का मैदान आयोजन स्थल बना तो उठे सवाल

बैकुंठपुर के रामानुज मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय पर्व,राजनीतिक कार्यक्रमों,राज्योत्सव,जिला गटन उत्सव, गरबा और रावण दहन जैसे आयोजनों के लिए मैदान का इस्तेमाल होता रहा है,बड़े कार्यक्रमों के लिए मंच,पंडाल और अन्य व्यवस्थाएं तैयार करने में समय लगता है,इस दौरान मैदान के कुछ हिस्सों का सामान्य उपयोग सीमित हो सकता है,इसी स्थिति को लेकर सवाल उठे कि जिस परिसर का उपयोग विद्यार्थी खेलकूद और अन्य गतिविधियों के लिए करते हैं,वहां बार-बार आयोजन होने पर उनकी जरूरतों का ध्यान कैसे रखा जाता है,मुद्दा कार्यक्रमों के आयोजन का विरोध करना नहीं, बल्कि ऐसा संतुलन बनाने का है जिसमें सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रम भी हों और विद्यार्थियों के लिए खेल का स्थान भी सुरक्षित रहे,दैनिक घटती-घटना में इस विषय को उठाए जाने के बाद चर्चा का दायरा बढ़कर पूरे शहर में खेल मैदानों की उपलब्धता तक पहुंच गया है,यदि वैकल्पिक मैदान उपलब्ध हो, तो बड़े आयोजनों का दबाव मिनी स्टेडियम से कम किया जा सकता है, इससे स्कूल परिसर के नियमित उपयोग और सार्वजनिक आयोजनों के बीच बेहतर संतुलन

हैचरी की जमीन पर शहर के बीचोंबीच स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव,सीए प्रशांत गुप्ता ने गिनाए फायदे

बैकुंठपुर में बंद पड़ी सरकारी हैचरी की जमीन को लेकर भी सीए प्रशांत गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण विकल्प सामने रखा है,उनका कहना है कि यदि हैचरी को भविष्य में दोबारा शुरू नहीं किया जाना है या इसे किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग पर विचार होता है,तो इस जमीन का उपयोग बैकुंठपुर के लिए एक बेहतर स्टेडियम विकसित करने में किया जा सकता है,उनके अनुसार,यह स्थान शहर के भीतर और मुख्य मार्ग के नजदीक होने के कारण खेल सुविधाओं के विकास के लिए उपयुक्त साबित हो सकता है,प्रशांत गुप्ता के मुताबिक, जमीन का कुछ हिस्सा निचले स्तर पर है,लेकिन समतलीकरण करार कर यहां व्यवस्थित स्टेडियम तैयार किया जा सकता है, इस स्थान की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहां से पुलिस लाइन,नगर पालिका और शहर के प्रमुख हिस्सों तक पहुंच आसान हो सकती है, इसके अलावा,एसईसीएल मैदान के सामने तथा प्रेमबाग कॉलोनी के पीछे स्थित होने के कारण यह क्षेत्र शहर के खेल और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है,उन्होंने इस स्थान की पहुंच को भी इसकी बड़ी उपयोगिता बताया,प्रस्ताव के अनुसार, स्टेडियम तक पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग की ओर से प्रवेश किया जा सकता है, इसके अलावा हैचरी के मुख्य मार्ग वाले रास्ते और प्रेमबाग कॉलोनी के पीछे मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग से भी आवागमन की व्यवस्था विकसित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है, इससे अलग-अलग दिशाओं से स्टेडियम तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा और बड़े आयोजनों के दौरान यातायात का दबाव भी व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है,सीए प्रशांत गुप्ता का मानना है कि पर्याप्त योजना के साथ यहां दर्शकों के प्रवेश,पार्किंग,खेल गतिविधियों और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है। यदि जमीन की उपलब्धता, स्वामित्व, तकनीकी व्यवहार्यता और प्रशासनिक अनुमति अनुकूल रहती है,तो यह स्थान बैकुंठपुर को एक व्यवस्थित स्टेडियम देने का विकल्प बन सकता है,उनका सुझाव है कि शहर के बीचोंबीच उपलब्ध इस जमीन की उपयोगिता पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हालांकि,हैचरी को बंद रखने अथवा दूसरी जगह स्थानांतरित करने और उसकी जमीन पर स्टेडियम निर्माण का निर्णय संबंधित विभागों की नीति,भूमि की स्थिति और तकनीकी जांच के बाद ही संभव होगा, फिलहाल,यह प्रस्ताव बैकुंठपुर में स्थायी खेल मैदान की जरूरत को लेकर चल रही चर्चा में एक नया विकल्प प्रस्तुत करता है।

राजीव गुप्ता का प्रस्ताव-एसईसीएल मैदान को आम लोगों के लिए खोलें

कांग्रेस नेता राजीव गुप्ता ने बैकुंठपुर और आसपास की ग्राम पंचायतों में खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त तथा व्यवस्थित मैदानों की कमी का मुद्दा उठाया है, उनका कहना है कि शहर के बीच स्थित रामानुज मिनी स्टेडियम साल के कई अवसरों पर आयोजनों और उनकी तैयारियों के कारण नियमित खेल गतिविधियों के लिए उपलब्ध नहीं रह पाता,ऐसे में एसईसीएल ऑफिसर्स कॉलोनी के भीतर स्थित मैदान को शहरवासियों के लिए

नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशियों से मांगी जा सकती है ठोस कार्ययोजना

आगामी नगर पालिका चुनाव के संदर्भ में खेल मैदान का मुद्दा शहर के विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है,नागरिकों के सामने अब यह अवसर है कि वे प्रत्याशियों से केवल सामान्य आश्वासन नहीं, बल्कि स्पष्ट योजना के बारे में भी सवाल पूछें, क्या एसईसीएल प्रबंधन से औपचारिक बातचीत की जाएगी? क्या मैदान के लिए प्रवेश द्वार बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा? क्या बंद पड़ी हैचरी की जमीन की उपलब्धता का परीक्षण कराया जाएगा? विकास और रखरखाव का खर्च कौन उठाएगा? क्या मैदान को नियमित खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा? और प्रस्ताव को लागू करने की समयसीमा क्या होगी? इन सवालों पर सभी प्रत्याशियों के विचार सामने आने से नागरिकों को अलग-अलग प्रस्तावों और उनकी व्यावहारिकता को समझने का अवसर मिलेगा। खेल मैदान का मुद्दा किसी एक दल तक सीमित नहीं है, यह शहर के बच्चों, युवाओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों की जरूरत से जुड़ा है।

अब बयानों से आगे बढ़कर जमीन पर काम की जरूरत

बैकुंठपुर में खेल मैदान को लेकर उठी चर्चा ने शहर की एक बुनियादी जरूरत को सामने रखा है। रामानुज मिनी स्टेडियम में सार्वजनिक आयोजनों और विद्यार्थियों की खेल गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है,इसके साथ ही,एसईसीएल मैदान और बंद पड़ी हैचरी की जमीन जैसे संभावित विकल्पों की व्यवहारिकता का आकलन भी जरूरी है, राजीव गुप्ता और सीए प्रशांत गुप्ता के विचारों के बाद अब संबंधित प्रशासन,नगर निकाय और एसईसीएल प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी,किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए जमीन की स्थिति,स्वामित्व,अनुमति,लागत,सुरक्षा और संचालन संबंधी पहलुओं पर स्पष्टता आवश्यक है, दैनिक घटती-घटना में मिनी स्टेडियम के मुद्दे को उठाए जाने के बाद शुरू हुई यह चर्चा तभी सार्थक परिणाम दे सकेगी,जब वैकल्पिक मैदान के लिए ठोस प्रस्ताव,जिम्मेदार एजेंसी और समयसीमा तय हो,शहर को केवल आयोजन कराने की जगह नहीं, बल्कि ऐसी सार्वजनिक सुविधा चाहिए जिसका उपयोग सालभर बचने, युवा, खिलाड़ी और आम नागरिक कर सकें,अब बैकुंठपुर के सामने सवाल साफ है-क्या शहर को एक व्यवस्थित खेल मैदान और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल होगी, या यह मुद्दा चुनावी चर्चा तक ही सीमित रह जाएगा?

बनाने और कॉलोनी की सुरक्षा के बीच संतुलन कायम करने का रास्ता निकल सकता है।

हाईमास्ट लाइट,सार्वजनिक जिम और पार्किंग का सुझाव

राजीव गुप्ता ने मैदान को उपयोगी बनाने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाओं का सुझाव भी दिया है,इसमें हाईमास्ट लाइट,दौड़ने और टहलने के लिए उपयुक्त व्यवस्था तथा मैदान के एक किनारे सार्वजनिक जिम विकसित करना शामिल है,उनके अनुसार, मैदान में पर्याप्त खुली जगह और पार्किंग की संभावना होने से इसे शहर की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा सकता है,उन्होंने यह विचार भी रखा है कि बंद पड़ी हैचरी के विस्थापन के बाद उसके सामने की जमीन के किसी हिस्से में शहर की जरूरत के अनुरूप ऑडिटोरियम बनाया जा सके,ऐसी स्थिति में बड़े कार्यक्रमों के दौरान एसईसीएल मैदान का उपयोग पार्किंग सहित अन्य सहायक व्यवस्थाओं के लिए भी किया जा सकता है,हालांकि,ये सभी प्रस्ताव फिलहाल विचार और सुझाव के स्तर पर हैं,इनके क्रियान्वयन के लिए संबंधित जमीन की स्थिति, स्वामित्व,उपलब्धता,विकास लागत और संबंधित विभागों की अनुमति की जानकारी जरूरी होगी, केवल मैदान उपलब्ध होने से परियोजना अपने आप पूरी नहीं हो जाती, उसके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी भी तय करनी होगी।

सीए प्रशांत गुप्ता ने भी एसईसीएल मैदान को बताया विकल्प

दूसरी ओर,भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार बताए जा रहे सीए प्रशांत गुप्ता ने भी एसईसीएल मैदान को शहर में विभिन्न आयोजनों के लिए संभावित विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है,उनका कहना है कि यह मैदान शहर के भीतर स्थित है,लेकिन शैक्षणिक संस्थानों से दूर होने के कारण बड़े कार्यक्रमों के लिए उपयोगी हो सकता है,उन्होंने इसे दो तरफ से प्रवेश द्वार के साथ बहुउपयोगी मैदान के रूप में विकसित करने की

कॉलेज और अन्य परिसरों की स्थिति ने बढ़ाई जरूरत

राजीव गुप्ता ने अपने विचार में कॉलेज परिसर और अन्य उपलब्ध जमीनों के इस्तेमाल से जुड़ी परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है, उनके अनुसार, कॉलेज कैम्पस में एसपी कार्यालय चलने से कुछ स्थानों की उपलब्धता प्रभावित हुई है,यदि शहर के अन्य सार्वजनिक और शैक्षणिक परिसरों में भी खेल गतिविधियों के लिए जगह सीमित है,तो यह स्थिति नगर नियोजन के स्तर पर समीक्षा की मांग करती है,शहर में कितने मैदान उपलब्ध हैं, उनमें से कितने नियमित खेल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और किन स्थानों को बेहतर बनाकर आम नागरिकों के लिए खोला जा सकता है-इन सवालों पर प्रशासन और संबंधित संस्थानों को तथ्यात्मक जानकारी सामने रखनी चाहिए, खेल मैदान केवल खिलाड़ियों के अभ्यास का स्थान नहीं होता। बच्चों के शारीरिक विकास, युवाओं की खेल प्रतिभा, बुजुर्गों की सैर और नागरिकों की दैनिक गतिविधियों के लिए भी सार्वजनिक खुली जगह जरूरी है, इसलिए इस विषय का समाधान केवल किसी एक मैदान को उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शहर की दीर्घकालीन जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए।

कल्पना रखी है,प्रशांत गुप्ता की सोच में मैदान को शासकीय,अशासकीय और निजी आयोजनों के लिए उपयोगी बनाने का पहलू प्रमुख है,वहीं,राजीव गुप्ता ने मैदान को आम नागरिकों के लिए नियमित रूप से खोलने,खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया है,दोनों नेताओं के विचारों में एसईसीएल मैदान का उपयोग बढ़ाने की बात सामने आती है, लेकिन इसके इस्तेमाल का उद्देश्य और संचालन की रूपरेखा स्पष्ट करना जरूरी होगा, क्या मैदान मुख्य रूप से खेल गतिविधियों के लिए होगा? क्या वहां बड़े आयोजन भी होंगे? यदि दोनों तरह की गतिविधियां होंगी, तो उनके लिए समय और स्थान कैसे निर्धारित किया जाएगा? इन सवालों का जवाब विस्तृत योजना से ही मिल सकेगा।

एसईसीएल मैदान की मौजूदा स्थिति भी बड़ी चुनौती

एसईसीएल मैदान को विकल्प के रूप में विकसित करने की चर्चा के साथ उसकी वर्तमान स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है,उपलब्ध विवरण और साझा तस्वीरों में मैदान के कुछ हिस्सों में रखरखाव की कमी दिखाई देती है,ऐसे में इसे नियमित खेलकूद या बड़े आयोजनों के लिए उपयोगी बनाने से पहले सफाई, समतलीकरण, सुरक्षा,प्रकाश व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं का आकलन करना होगा, मैदान ऑफिसर्स कॉलोनी के भीतर स्थित होने के कारण आम नागरिकों की नियमित पहुंच भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है,यदि मुख्य मार्ग से अलग प्रवेश द्वार बनाया जाता है,तो उसके लिए एसईसीएल प्रबंधन की सहमति,सुरक्षा व्यवस्था और प्रवेश के नियम तय करने होंगे,यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि मैदान का रखरखाव कौन करेगा और विकास के होने वाला खर्च किस मद से आएगा,राजीव गुप्ता ने अपने सुझाव में कॉलोनी की सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा दोनों को ध्यान में रखने की बात कही है, उनके प्रस्ताव के अनुसार,उचित फेंसिंग और अलग प्रवेश व्यवस्था के जरिए मैदान को आम नागरिकों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, हालांकि, इसकी व्यवहारिकता एसईसीएल प्रबंधन के निर्णय और तकनीकी आकलन पर निर्भर करेगी।

